स्व लेखा परीक्षण

इस वित्तीय वर्ष के दौरान कुल देय 192 शाखाओं में से 90%, 173 शाखाओं में सेल्फ ऑडिट किया गया।

आई एस ऑडिट

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान प्रधान कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों एवं कुछ शाखाओं का आई एस ऑडिट करवाया गया।

प्रशासनिक इकाइयों का आंतरिक निरीक्षण

प्रधान कार्यालय और समस्त 5 क्षेत्रीय कार्यालयों का इस वर्ष के दौरान आन्तरिक निरीक्षण किया गया।

बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति

बोर्ड लेखा परीक्षा समिति का गठन भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड तथा राज्य सरकार द्वारा नामांकित निदेशकों को शामिल कर किया गया है। समिति की अध्यक्षता भारतीय स्टेट बैंक के नामित निदेशक द्वारा की जाती है। इस वित्तीय वर्ष में बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति की चार बैठकें आयोजित की गयी।

नाबार्ड निरीक्षण

बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35 (6) के अन्तर्गत नाबार्ड द्वारा दिनांक 31.03.2024 की वित्तीय स्थिति पर बैंक का अंकेक्षण किया गया है। उक्त अंकेक्षण रिपोर्ट (दिनांक 16.08.2024) की आख्या दिनांक 14.10.2024 को नाबार्ड को प्रस्तुत की जा चुकी है।

प्रबंधन लेखा परीक्षा

बैंक का प्रबंधन लेखा परीक्षा भारतीय स्टेट बैंक द्वारा दिनांक 31.03.2023 की वित्तीय स्थिति पर किया गया। रिपोर्ट का समापन निर्धारित समय में किया गया।

बैंक की पॉलिसी संरचना

बैंकिंग के सभी क्षेत्रों में नीति निर्धारित करने एवं निरन्तरता बनाये रखने हेतु एक नीतिगत रूपरेखा तैयार की गई है। दिनांक 31.03.2025 की तिथि में हमारे बैंक की निम्नलिखित नीतियां विधिवत रूप से बोर्ड की बैठक में बोर्ड द्वारा अनुमोदित/ समीक्षा की गई है।

नीतियों की सूची

1. ऋण नीति
2. स्वर्ण आभूषणों के विरूद्ध ऋण नीति
3. सिबिल नीति
4. कोलेटरल/क्रेडिट जोखिम प्रबंधन नीति
5. एएमएच रूपरेखा नीति
6. एनपीए प्रबंधन
7. सतर्कता नीति
8. धोखाधड़ी प्रबंधन नीति
9. मुखबिर नीति
10. जांच एजेंसियों को नियुक्त करने के लिए नीति
11. आंतरिक लेखा नीति
12. समवर्ती लेखा नीति
13. अनुपालना लेखा नीति
14. निवेश नीति
15. केवाईसी/एएमएल नीति
16. अनआदरित चैक एवं इलेक्ट्रानिक भुगतान प्रणाली नीति
17. मूल्यह्रांस नीति
18. अभिलेख अवधारण नीति
19. ई-अपशिष्ट नीति
20. डीईएएफ नीति
21. परिसर नीति
22. शिकायत प्रबंधन नीति
23. अनुपालना नीति
24. प्रशिक्षण नीति
25. स्थानान्तरण नीति
26. अवकाश नीति
27. मेडिकल इन्श्योरेंस नीति
28. मानव संसाधन नीति (मित्रा समिति की सिफारिश पर)
29. वकीलों की नियुक्ति के लिए नीति
30. शिकायत एवं निवारण नीति
31. बीसी नीति
32. जोखिम प्रबंधन नीति
33. आस्ति दायित्व प्रबंधन नीति
34. आईसीएएपी
35. मुआवजा नीति
36. आउटसोर्सिंग नीति
37. ग्राहक मूल्य वृद्धि एवं तृतीय पक्ष उत्पाद (क्रास सेलिंग) नीति

38. आईएस सुरक्षा नीति
39. आईटी नीति
40. आईएस लेखा नीति
41. मोबाईल बैंकिग नीति
42. साइबर नीति
43. क्रय नीति
44. इंटरनेट बैंकिग नीति
45. एटीएम परिचालन नीति
46. परिसर किराया नीति
47. व्यापार निरंतरता और आपदा प्रबंधन नीति
48. बैंक जमा नीति
49. शाखा भ्रमण नीति
50. बोर्ड लेखा समिति नीति
51. सीआईसी की सदस्यता
52. एनपीए की प्रणाली जेनरेशन नीति
53. भुगतान एवं निपटान प्रणाली
54. बैंकिग ओमबडसमेन नीति
55. रोकड़ प्रबंधन नीति
56. अनुपालना विभाग
57. निरीक्षण निष्कर्ष की अनुपालना
58. विवेकपूर्ण मानदंडों की अनुपालना
59. वित्तीय शक्तियों का प्रतिनिधान
60. आईबीपीसी एवं पीएसएलसी
61. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निशेध और निवारण पर नीति
62. एमएसएमई पुनर्वास नीति
63. बीएसबीडीए नीति
64. समझौता नीति
65. चैक संग्रहण नीति
66. व्यवसायिक कोर्स के लिये इंटर्नशिप नीति
67. नकली नोट का पता लगाने की नीति
68. ग्राहक अधिकार नीति
69. अचल संपति नीति
70. स्टाफ जवाबदेही नीति
71. डॉर-स्टैप बैंकिंग नीति
72. पूरक ऑडिट नीति
73. क्रेडिट ऑडिट नीति
74. कानूनी ऑडिट नीति
75. सेफ डिपॉसिट/लॉकर नीति
76. पूंजी प्रबंधन नीति
77. स्टॉक ऑडिट नीति
78. प्रबंधन ऑडिट नीति
79. साइबर संकट प्रबंधन योजना (Cyber Crisis Management Plan)

जोखिम प्रबंधन

यूजीबी के पास विभिन्न प्रकार के जोखिमों का आकलन करने और उन्हें कम करने के लिए एक प्रभावी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है। बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीति मौजूद है।

जोखिम प्रबंधन विभाग बैंक के महाप्रबंधक (प्रशासन) की अध्यक्षता में त्रैमासिक अंतराल पर सभी विभागों के सभी विभागाध्यक्षों की बैठक बुलाता है। जोखिम प्रबंधन समिति विभागवार विभिन्न जोखिमों का आंकलन और पहचान करती है और प्रभावी नियंत्रण के माध्यम से जोखिमों को कम करने के लिए रणनीति तैयार करती है। कार्यवाही की आगे समीक्षा बैंक के अध्यक्ष द्वारा की जाती है।

बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में निम्नलिखित जोखिमों की पहचान की है और उन्हें कम करने हेतु कार्यवाही की गई है:

1. **तरलता जोखिम और ब्याज दर जोखिम:** बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित आस्ति देयता समिति (ALCO समिति) है, जो तरलता की स्थिति और ब्याज दर की समीक्षा करने के लिए आवश्यकता पड़ने पर बैठक करती है। बैंक ने बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित एएलएम नीति भी तैयार की है और नियमित रूप से ALCO/बोर्ड को तरलता पैरामीटर और ब्याज दर परिदृश्य पेश कर रहा है। बैंक ने अमेरिका और स्विट्जरलैंड में बैंकिंग अस्थिरता को देखते हुए बैंक की तरलता की स्थिति का भी आंकलन किया है और बैंक ने तरलता और बाजार जोखिम को संतोषजनक पाया है।

2. **परिचालन जोखिम:** पिछले वित्तीय वर्ष की तरह, यूजीबी ने सभी शाखाओं में आरसीएसए (जोखिम और नियंत्रण स्व-मूल्यांकन अभ्यास) के माध्यम से परिचालन जोखिम को पहचानने और कम करने की प्रक्रिया फिर से पूरी की।

3. **क्रेडिट जोखिम:** यूजीबी के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित ऋण और वसूली नीति है। बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान बर्ड-लखनऊ, एसबीआईआरबी-हैदराबाद, सीएबी पुणे, नाबार्ड आदि जैसे अन्य बाहरी संस्थानों से प्रशिक्षण के अलावा, इन हाउस ट्रेनिंग सिस्टम यानी यूजीबी लर्निंग सेंटर के माध्यम से क्रेडिट मूल्यांकन के लिए अधिकारियों को ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रशिक्षण प्रदान किया है। कृषि अग्रिमों के लिए एसबीआईआरबी, हैदराबाद के सहयोग से यूजीबीएलसी द्वारा दो विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए थे।
4. **अनुपालन जोखिम:** यूजीबी के पास प्रभावी ऑडिट नीति लागू है। बैंक शाखाओं में नियमित आरएफआईए ऑडिट और समवर्ती ऑडिट आयोजित कर रहा है। बैंक को किसी भी वित्तीय दंड का सामना नहीं करना पड़ा है और वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान बैंक पर लागू सभी कानूनों और विनियमों का अनुपालन करता है।
5. **बाहरी पर्यावरण जोखिम:** उत्तराखण्ड राज्य प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त है। यदि कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो इसका बैंक के समग्र व्यवसाय पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और इससे क्रेडिट और परिचालन जोखिम हो सकता है जिसके परिणामस्वरूप प्रतिष्ठा को भी खतरा हो सकता है। इन जोखिमों को कम करने के लिए, यूजीबी ने प्रभावी बिजनेस निरंतरता योजना के माध्यम से ऐसी अप्रत्याशित स्थितियों के मामले में सभी शाखाओं में निर्बाध रूप से बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए मॉक ड्रिल अभ्यास शुरू किया है।

नाबार्ड के दिशा-निर्देशों पर बैंक द्वारा विभिन्न जोखिमों जैसे-तरलता जोखिम, क्रेडिट जोखिम एवं ब्याज दर जोखिम की पहचान, विश्लेशण एवं कमी तनाव-परीक्षण फ्रेमवर्क शुरू किया गया है। इसी के साथ क्रेडिट एवं संचालन जोखिमों के प्रबंधन के लिए विशेष नीतियां जारी की गयी हैं।

वित्तीय समावेशन

वित्तीय वर्ष 2024-25 में बैंक ने ग्राहक सेवा केंद्रों (CSPs) के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में उल्लेखनीय प्रगति की है। प्रत्येक CSP को किओस्क सॉफ्टवेयर और 200 उन्नत एंड्रॉइड आधारित POS MATM उपकरणों से सुसज्जित किया गया है, जो ओलिव पोर्टल से एकीकृत हैं, जिससे दूरस्थ और वंचित क्षेत्रों में ग्राहकों को निर्बाध बैंकिंग अनुभव प्राप्त हो रहा है।

कुल लेन-देन

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान CSP चैनल के माध्यम से कुल 10,20,879 लेन-देन किए गए, जिनका मूल्य ₹ 351.23 करोड़ रहा। यह पिछले वर्ष के 6,88,703 लेन-देन (₹ 246.23 करोड़) के सापेक्ष लेन-देन की संख्या में 50% और मूल्य में 43% की वृद्धि को दर्शाता है।

लेन-देन मात्रा में वृद्धि

CSP चैनल के माध्यम से कुल लेन-देन मात्रा में उल्लेखनीय 43% की वृद्धि दर्ज की गई, जो हमारे ग्राहकों के बीच CSP नेटवर्क पर बढ़ते विश्वास और निर्भरता को दर्शाती है। यह वृद्धि बैंकिंग आवश्यकताओं के लिए CSP मॉडल की प्रभावशीलता का प्रमाण है।

सक्रियता एवं प्रोत्साहन अभियान

वर्षभर बैंक द्वारा ग्राहक सेवा केंद्रों (CSPs) और कॉर्पोरेट बिजनेस करेस्पोंडेंट्स (CBCs) की सक्रियता एवं प्रोत्साहन के लिए कई विशेष अभियान आयोजित किए गए। इन पहलों ने CSP नेटवर्क की भागीदारी और प्रदर्शन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

बचत खाता वृद्धि

CSPs के माध्यम से कुल 40,450 नए बचत खाते खोले गए, जिनमें 31 मार्च 2025 तक कुल ₹ 12.61 करोड़ की जमा राशि रही, जो ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में वित्तीय भागीदारी के विस्तार को दर्शाता है।

वित्तीय समावेशन में उपलब्धियाँ; सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में सफलता

बैंक ने पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और अटल पेंशन योजना जैसी प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के अंतर्गत लक्ष्यों से अधिक प्रदर्शन कर वित्तीय समावेशन को मजबूती प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

पीएमएसबीवाई (प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना)

बैंक द्वारा इस वित्तीय वर्ष के दौरान 88,884 पीएमएसबीवाई में नामांकन किए गए, जो निर्धारित लक्ष्य 75,765 का 116% है। दिनांक 31.03.2025 तक बैंक द्वारा प्रधानमन्त्री सुरक्षा बीमा योजना के अंर्तगत कुल 5,82,404 ग्राहकों को नामांकित किया गया है।

पीएमजेजेबीवाई (प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना)

बैंक द्वारा इस वित्तीय वर्ष के दौरान 64,356 पीएमजेजेबीवाई में नामांकन किए गए, जो निर्धारित लक्ष्य 62,138 का 103% है। दिनांक 31.03.2025 तक बैंक द्वारा प्रधानमन्त्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंर्तगत कुल 2,80,698 ग्राहकों को नामांकित किया गया है।

अटल पेंशन योजना

बैंक द्वारा इस वित्तीय वर्ष के दौरान 29,462 अटल पेंशन योजना में नामांकन किए गए, जो निर्धारित लक्ष्य 26,100 का 112% है। दिनांक 31.03.2025 तक बैंक द्वारा अटल पेंशन योजना के अंतर्गत कुल 1,73,277 ग्राहकों को नामांकित किया गया है।

अटल पेंशन योजना में राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान: बैंक को अटल पेंशन योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए PFRDA द्वारा निम्नलिखित पुरस्कार प्रदान किए गए:

- वार्षिक उपलब्धि पुरस्कार
- वार्षिक उत्कृष्ट प्रदर्शन पुरस्कार
- मल्टीपल विनिंग वेडनसडे पुरस्कार
- अटल पेंशन योजना ओलंपिक में चेयरमैन क्लब में चयन

वित्तीय समावेशन में क्रांति: पोर्टेबल एंड्रॉइड माइक्रो एटीएम्स (MATM)

वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, बैंक ने 200 पोर्टेबल एंड्रॉइड माइक्रो एटीएम (MATMs) ग्राहक सेवा प्रदाताओं (CSPs) को उपलब्ध कराए गए। इन आधुनिक उपकरणों से लेन-देन की मात्रा में उल्लेखनीय वृद्धि की है, जिससे CSPs को सशक्तता मिली है और उनकी आय में भी बढ़ोतरी हुई है। यह पहल ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में डिजिटल बैंकिंग सेवाओं की पहुँच और सुविधा में एक मील का पत्थर साबित हुई है। MATMs की उन्नत विशेषताएँ जैसे त्वरित खाता खोलना, आधार सीडिंग, रूपये कार्ड के माध्यम से लेन-देन, ग्रीन पिन जनरेशन, अतिरिक्त सुविधाओं को जोड़ने के लिए आगामी अपडेट की योजना, इत्यादी हैं। ये उपकरण अब पहले से भी अधिक बहुउपयोगी और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनते जा रहे हैं, जिससे CSPs की सेवा दक्षता और ग्राहकों का अनुभव दोनों बेहतर हुआ है।

इन उपकरणों हेतु नाबार्ड द्वारा ₹ 45.00 लाख की सब्सिडी प्रदान की गई, जिससे डिजिटल बैंकिंग नेटवर्क का विस्तार वंचित क्षेत्रों तक हो सका।

स्वच्छता एवं वित्तीय साक्षरता के प्रचार हेतु नुक्कड़ नाटक का आयोजन

इस वर्ष, बैंक ने उत्तराखण्ड के विभिन्न क्षेत्रों में 15 नुक्कड़ नाटकों का सफल आयोजन किया। स्थानीय समुदायों से संवाद स्थापित करने हेतु नाटक और मंचन की प्रभावशाली शक्ति का उपयोग करते हुए, इन प्रस्तुतियों का आयोजन "**स्वच्छता ही सेवा, स्वभाव स्वच्छता - संस्कार स्वच्छता**" थीम के अंतर्गत किया गया। इन नुक्कड़ नाटकों

का उद्देश्य न केवल हमारे दैनिक जीवन में स्वच्छता के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना था, बल्कि वित्तीय मामलों में भी पारदर्शिता और साफ-सफाई बनाए रखने के महत्व को समझाना था।

डिजिटल वित्तीय साक्षरता के माध्यम से समुदायों को सशक्त बनाना: 500+ DFLP शिविरों का आयोजन

उत्तराखंड के लोगों के प्रति अपनी गहरी प्रतिबद्धता के तहत, बैंक यह समझता है कि नवीनतम बैंकिंग रुझानों की जानकारी देना और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते खतरे से लोगों की रक्षा करना अत्यंत आवश्यक है। राज्य के कई निवासी दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करते हैं, जहाँ धोखाधड़ी की घटनाएँ बढ़ रही हैं और लोग अपनी मेहनत की कमाई गंवा रहे हैं।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए, बैंक ने सक्रिय पहल करते हुए अपनी 291 शाखाओं के माध्यम से 428 डिजिटल वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम शिविरों का आयोजन किया। इसके अतिरिक्त, बैंक के दो वित्तीय साक्षरता परामर्शदाता (FLCs) के सहयोग से अतिरिक्त 300 शिविर आयोजित किए गए, जिनके माध्यम से शहरी और ग्रामीण दोनों समुदायों के हजारों लोगों तक पहुँचा गया।

बैंक सखियों से बैंक CSP तक वित्तीय समावेशन की ओर एक सशक्त कदम

लैंगिक समानता और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत, बैंक ने गर्व के साथ 55 बैंक सखियों (BCs) को बैंक CSPs के रूप में नियुक्त किया है। यह पहल न केवल इन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर देती है, बल्कि इन्हें अपने समुदायों का अभिन्न हिस्सा भी बनाती है।

बैंक सखियों की यह नियुक्ति ग्रामीण क्षेत्रों और वंचित समुदायों में बैंकिंग सेवाओं की पहुँच बढ़ाने में सेतु का कार्य कर रही है। बैंक द्वारा इन्हें ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान किया गया है।

लक्सर शाखा की बैंक सखी 'सुश्री गुलफरीन' की सफलता इस प्रयास की सशक्त मिसाल है। मात्र एक वित्तीय वर्ष में सुश्री गुलफरीन ने 911 पीएमजेडीवाई खाते खोले, जो उनके समर्पण और बैंकिंग क्षेत्र में महिलाओं की प्रभावशाली भूमिका का प्रमाण है।

महिला वर्ल्ड बैंक और नाबार्ड के सहयोग से CSP चैनल को सशक्त बनाना: जन धन प्लस पहल

वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और हमारे ग्राहक सेवा प्रदाताओं को सशक्त बनाने के निरंतर प्रयासों के अंतर्गत, बैंक ने महिला वर्ल्ड बैंक और नाबार्ड के सहयोग से जन धन प्लस कार्यक्रम का सफलतापूर्वक शुभारंभ किया।

महिला वर्ल्ड बैंक ने नाबार्ड के सहयोग से बैंक के छह क्षेत्रीय कार्यालयों में CSP चैनल से जुड़े व्यक्तियों के लिए प्रत्यक्ष प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए।

इस पहल के परिणाम स्वरूप PMJDY खातों को खोलने में CSP का योगदान 32% से बढ़कर 55% हो गया, जो इस कार्यक्रम की सफलता और वित्तीय समावेशन को गति देने में इसकी प्रभावशीलता को दर्शाता है।

यूआईडीएआई के अंतर्गत पृथक रजिस्ट्रार के रूप में आधार नामांकन एवं अपडेट केंद्र

बैंक की 29 शाखाओं को आधार नामांकन एवं अद्यतन केंद्रों के संचालन हेतु नामित किया गया है। इस पहल के अंतर्गत अब हमारा बैंक आधार संबंधी समस्त कार्यों के लिए एक पृथक रजिस्ट्रार बन गया है। यह कदम न केवल राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप है, बल्कि आधार नामांकन एवं अद्यतन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित कर आम जनता को अधिक द्रुत, सुलभ और कुशल सेवाएँ प्रदान करने में भी सहायक है।

वित्तीय समावेशन का विस्तार: वित्तीय साक्षरता वैन के माध्यम से

वर्तमान में बैंक के पास 15 वित्तीय साक्षरता वाहन हैं, जो एटीएम सुविधा से सुसज्जित हैं और राज्यभर में भ्रमण कर लोगों को आधुनिक बैंकिंग सेवाओं के बारे में जागरूक करते हैं। इनमें मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन, इंटरनेट बैंकिंग, और UPI आधारित वॉलेट शामिल हैं।

ये वाहन विशेष रूप से चार धाम यात्रा, हेमकुंड साहिब जैसे तीर्थ स्थलों

और औली, धनोल्टी जैसे प्रमुख पर्यटक स्थलों पर लोगों से जुड़ने में अत्यंत प्रभावी सिद्ध हुए हैं। यह पहल वित्तीय साक्षरता और समावेशन के क्षेत्र में बैंक की सक्रिय भूमिका को दर्शाती है।

11 नए कॉरपोरेट और बिजनेस करेस्पोंडेंट्स (BC) का पैनल में शामिल किया जाना

बैंकिंग सेवाओं की पहुँच को विस्तार देने और ग्राहक सेवा प्रदाता (BCs) चैनल को सुदृढ़ करने के हमारे निरंतर प्रयासों के अंतर्गत, हमें यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि 11 नए कॉरपोरेट और

बिजनेस करेस्पोंडेंट्स (BCs) का सफलतापूर्वक पैनल में समावेश किया गया है।

जन सुरक्षा पोर्टल एवं परिवर्तन पोर्टल

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए ग्राहक अनुभव को सरल और बेहतर बनाने के हमारे प्रयासों के अंतर्गत, बैंक ने डिजिटल नामांकन और दावा निपटान प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण प्रगति की है।

बैंक अब जन सुरक्षा पोर्टल से जुड़ चुका है, जिससे ग्राहक इन योजनाओं में घर बैठे ऑनलाइन नामांकन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, एक अपडेट पर कार्य चल रहा है जिससे बैंक शाखाएँ जन सुरक्षा पोर्टल के माध्यम से सीधे दावा निपटान कर सकेंगी, जिससे बैंक टीमों और ग्राहकों दोनों के लिए एक सहज और एकीकृत सेवा अनुभव सुनिश्चित होगा।

प्रथम चरण में, PMJJBY दावा निपटान हेतु परिवर्तन पोर्टल को सफलतापूर्वक लागू किया गया है। यह नई प्रणाली क्षेत्रीय कार्यालय (RO) स्तर पर दावों को कुशलतापूर्वक संसाधित करने की सुविधा देती है, जिससे दावा निपटान की गति और पारदर्शिता में सुधार हुआ है।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में प्रभावी दावा निपटान: लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव

वर्तमान वित्त वर्ष में बैंक ने PMJJBY के 260 दावों का ₹ 5.20 करोड़ की राशि के साथ और PMSBY के 50 दावों का ₹ 1.00 करोड़ की राशि के साथ सफलतापूर्वक निपटान किया।

इन दावों के निपटान ने लाभार्थियों के परिवारों को न केवल वित्तीय सुरक्षा प्रदान की, बल्कि यह भी सिद्ध किया कि बैंक सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को वास्तव में जरूरतमंद लोगों तक पहुँचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

ग्रामीण बैंक ने पीड़ित परिवार को सौंपा दो लाख का चेक

मृतक आश्रित को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का चेक दिया

क्रॉस सेलिंग

एसबीआई लाइफ इन्श्योरेंन्स

बैंक एसबीआई लाइफ इन्श्योरेंन्स कॉरपोरेशन लिमिटेड का कॉरपोरेट ऐजेंट है जो वित्तीय समावेशन के हिस्से के रुप में बैंक के ग्राहकों की बीमा जरुरतों को पूरा करने के साथ ही बैंक की गैर ब्याज आय में वृद्धि करने में सहायक है। बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 18 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के साथ विगत वर्ष ₹ 22.43 करोड़ के सापेक्ष ₹ 26.45 करोड़ के नये प्रीमियम का व्यवसाय किया गया तथा विगत वर्ष ₹ 348.14 लाख के सापेक्ष ₹ 403.63 लाख कुल कमीशन आय अर्जित की गई।

एसबीआई जनरल इन्श्योरेंन्स

वर्ष 2016-17 से बैंक द्वारा वित्तपोशित उत्पादों के बीमा के साथ साथ योग्य तथा इच्छुक ग्राहकों हेतु जनरल इन्श्योरेंन्स के अन्य उत्पादों यथा स्वास्थ्य बीमा, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा के विपणन हेतु एसबीआई जनरल इन्श्योरेंन्स बिजनेस की शुरुआत की गई। बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान विगत वर्ष ₹ 10.09 करोड़ के सापेक्ष ₹ 12.36 करोड़ (22 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि) के नये प्रीमियम का व्यवसाय किया गया तथा विगत वर्ष ₹ 87.02 लाख के सापेक्ष ₹ 102.69 लाख (18 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि) कमीशन आय अर्जित की गई।

एसबीआई मयूचुअल फण्ड

वर्ष 2018 से बैंक द्वारा म्यूचुअल फण्ड के विपणन हेतु एसबीआई म्यूचुअल फण्ड के साथ अनुबंध किया गया। बैंक द्वारा विगत वर्ष 2023-24 के दौरान ₹ 4.86 लाख के 198 नये SIPs तथा ₹ 95.80 लाख का एकमुश्त निवेश व्यवसाय के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹ 7.18 लाख के 303 नये SIPs तथा ₹ 101.83 लाख का एकमुश्त निवेश व्यवसाय किया गया।

प्रौद्योगिकी के माध्यम से बैंकिंग में परिवर्तन: आईटी नवाचार का वर्ष (वित्तीय वर्ष 2024-25)

बैंक के सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) विभाग ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान बैंक में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने में प्रमुख भूमिका निभाई है। हमारा ध्यान ग्राहकों के अनुभव को बेहतर बनाने, आंतरिक कार्यक्षमताओं को बढ़ाने, सुरक्षा को मजबूत करने तथा नवीनतम डिजिटल तकनीकों को अपनाने पर केंद्रित रहा।

I. ग्राहकों को सशक्त बनाना और सेवाओं को बेहतर बनाना

- **UGB Insights: डेटा-आधारित ग्राहक सहभागिता**

बैंक ने "UGB Insights" नामक एक शक्तिशाली उपकरण विकसित किया है, जो हमारे रिलेशनशिप मैनेजर्स को ग्राहकों के डेटा का 360-डिग्री दृष्टिकोण प्रदान करता है। यह उपकरण उन्हें व्यक्तिगत सेवाएँ प्रदान करने, ग्राहकों की आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाने और सूचित निर्णय लेने में सक्षम बनाता है, जिससे ग्राहक संतुष्टि में वृद्धि और बैंक-ग्राहक संबंध मजबूत होते हैं। यह टूल बैंक कर्मचारियों को एक क्लिक में महत्वपूर्ण ग्राहक जानकारी उपलब्ध कराता है, जिससे बातचीत को सुव्यवस्थित किया जा सकता है और सेवा वितरण की गुणवत्ता में सुधार होता है।

- **व्यक्तिगत बैंकिंग**

  अब ग्राहक हमारी इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से व्यक्तिगत चेक बुक के लिए अनुरोध कर सकते हैं, जिससे उन्हें अधिक सुविधाजनक और अनुरूपित बैंकिंग अनुभव प्राप्त हो रहा है।

- **VKYC के माध्यम से सहज खाता खोलना**

  सुलभता और सुविधा को बढ़ाने हेतु, वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान बैंक ने 6,102 खाते VKYC के माध्यम से खोले गये। यह डिजिटल प्रक्रिया खाता खोलने को सरल बनाती है, दस्तावेजी प्रक्रिया को कम करती है, और ग्राहकों को दूरस्थ रूप से खाता खोलने की सुविधा प्रदान करती है।

- **UPI Lite**

  बैंक ने UPI Lite को लाइव कर दिया है, जिससे छोटी राशि के लेन-देन तेज और सरल हो गए हैं।

- **भारत कनेक्ट (पूर्व में BBPS)**

  भारत कनेक्ट, जो कि बिल भुगतान की सुविधा प्रदान करता है, अब मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग दोनों पर उपलब्ध है।

II. आंतरिक संचालन को सुव्यवस्थित करना और कार्यकुशलता बढ़ाना

- **UGB My Bank पोर्टल: केंद्रीकृत सूचना केंद्र**

  "UGB My Bank पोर्टल" कर्मचारियों के लिए एक समग्र आंतरिक संसाधन के रूप में कार्य करता है। यह पोर्टल सर्कुलर, नीतियाँ, उत्पाद कोड विवरण, शाखा प्रोफाइल, कर्मचारी संपर्क जानकारी और विक्रेता विवरण तक आसान पहुँच प्रदान करता है। यह केंद्रीकृत मंच आंतरिक संचार, ज्ञान साझाकरण और संचालन दक्षता को बेहतर बनाता है।

- **UGB Easy Approval पोर्टल: नोट स्वीकृति को डिजिटल बनाना**

  "UGB Easy Approval पोर्टल" को नोट स्वीकृति प्रक्रिया को तेज और सुव्यवस्थित करने के लिए विकसित किया गया है। यह उपयोगिता स्वीकृति प्रक्रिया को डिजिटाइज करती है, जिससे टर्नअराउंड समय घटता है और कुल कार्यकुशलता में सुधार होता है।

- **नया HRMS: मानव संसाधन प्रबंधन का आधुनिकीकरण**

  एक नवीन मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (HRMS) को लागू किया गया है, जो HR प्रक्रियाओं में अधिक दक्षता और स्वचालन लाता है। यह प्रणाली कर्मचारी प्रबंधन, वेतन प्रबंधन और अन्य HR संबंधित कार्यों को सरल और प्रभावी बनाती है।

- **डेली ब्रांच रिपोर्टिंग पोर्टल (DBPR): वास्तविक समय में जानकारी**

  "डेली ब्रांच रिपोर्टिंग पोर्टल (DBPR)" शाखाओं, CPCs और SARBs को दिन के अंत की रिपोर्ट कुशलतापूर्वक प्रस्तुत करने की सुविधा देता है। यह प्रणाली शाखा प्रदर्शन का समेकित अवलोकन प्रदान करती है, जिससे निगरानी और निर्णय-निर्धारण में सुधार होता है।

- **इन्वेंटरी यूटिलिटी: आईटी संपत्ति प्रबंधन में दक्षता**

  "इन्वेंटरी यूटिलिटी" विकसित की गई है, जो बैंक की आईटी परिसंपत्तियों का विस्तृत विवरण दर्ज करती है। इसमें RAM, एंटीवायरस स्थिति, IP एड्रेस, हार्ड डिस्क क्षमता, मॉडल, ऑपरेटिंग सिस्टम और MAC एड्रेस जैसी जानकारियाँ शामिल हैं। यह यूटिलिटी संपत्ति प्रबंधन, अनुरक्षण और योजना बनाने में सहायक है।

- **DEAF यूटिलिटी: केंद्रीकृत DEAF खाता प्रबंधन**

  "DEAF यूटिलिटी" जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि (DEAF) के तहत खातों के प्रबंधन को केंद्रीकृत करती है। यह शाखाओं द्वारा प्रक्रिया में हस्तक्षेप की आवश्यकता को समाप्त करती है, जिससे संचालन सरल और कुशल हो जाता है।

- **रिपोर्ट एवं रिटर्न का स्वचालन**

  बैंक ने कई महत्वपूर्ण रिपोर्टिंग प्रक्रियाओं को स्वचालित कर दिया है, जिनमें दैनिक रिपोर्ट, मासिक परिचालन रिटर्न, और

CM/GM/RM क्लब रिपोर्ट शामिल हैं। यह स्वचालन मानव संसाधन की बचत, त्रुटियों में कमी और समय पर रिपोर्टिंग सुनिश्चित करता है।

- **LOS के माध्यम से KCC खाता खोलना**

  वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान Loan Origination System (LOS) के माध्यम से 3061 KCC खाते खोले गए।

- **व्यक्तिगत एवं गोल्ड लोन के लिए LOS**

  वित्तीय वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में व्यक्तिगत ऋण और स्वर्ण ऋण के लिए LOS प्रणाली लाइव कर दिया गया है।

III. सुरक्षा को सुदृढ़ करना एवं जोखिमों को कम करना

- **साइबर सुरक्षा जागरूकता**

  अक्टूबर 2024 में बैंक ने "साइबर सुरक्षा जागरूकता माह" का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों और ग्राहकों को ऑनलाइन सुरक्षा के महत्व और साइबर खतरों से बचाव हेतु सर्वोत्तम उपायों के प्रति जागरूक करना था।

- **भेद्यता प्रबंधन (Vulnerability Management):**

  SBI ISD विभाग से प्राप्त सभी संवेदनशील साइट टिप्पणियों को समय पर संबोधित किया गया, जिससे हमारी प्रणालियों और डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित की गई।

- **लेन-देन सुरक्षा में वृद्धि**

  उच्च-मूल्य के लेन-देन की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए, आरंभ में ₹1 लाख से अधिक के RTGS/NEFT लेन-देन हेतु मुख्य कार्यालय की अतिरिक्त स्वीकृति की व्यवस्था लागू की गई। विश्लेषण के उपरांत यह सीमा क्रमिक रूप से ₹ 5 लाख और वर्तमान में ₹ 10 लाख कर दी गई है।

- **डेटा सुरक्षा**

  संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा और अनाधिकृत प्रकटीकरण को रोकने के लिए बैंक ने डेटा लीक प्रिवेंशन (DLP) और डेटा राइट्स मैनेजमेंट (DRM) प्रणाली को आधिकारिक ईमेल संरचना में लागू किया है।

- **फिशिंग जागरूकता**

  कर्मचारियों में फिशिंग जैसे सामान्य साइबर खतरे के प्रति जागरूकता बढ़ाने और उन्हें ऐसी घटनाओं की पहचान व प्रतिक्रिया के लिए प्रशिक्षित करने हेतु फिशिंग ईमेल मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया।

- **ADS कार्यान्वयन और प्रॉक्सी समाधान**

  नेटवर्क सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु बैंक के नेटवर्क में सभी प्रणालियों पर Active Directory Services (ADS) लागू की गई हैं तथा प्रॉक्सी समाधान भी लागू किए गए हैं।

- एंड-ऑफ-लाइफ (EOL) सिस्टम्स का हटाया जाना

  आईटी संरचना को सुरक्षित और अद्यतन बनाए रखने के लिए, सभी End-of-Life (EOL) और End-of-Service (EOS) सिस्टम्स को नेटवर्क से डिस्कनेक्ट कर दिया गया है।

- **धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन (Fraud Risk Management)**

  बैंक ने IMPS, UPI, ATM, ECOM और POS चैनलों के लिए फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट (FRM) एप्लिकेशन को सफलतापूर्वक लाइव किया है। हमारा विक्रेता C-Edge, FICO & Falcon Fraud Manager System की सहायता से एक एंटरप्राइज वाइड फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट सॉल्यूशन (EFRMS) लेकर आया है, जो सभी चैनलों को कवर करेगा और धोखाधड़ी से निपटने के लिए एक अधिक प्रभावी समाधान प्रदान करेगा। FRM प्रणाली सभी लेन-देन की निगरानी करती है और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी की गतिविधि की रीयल टाइम या नियर रीयल टाइम में पहचान कर ग्राहक को सूचित करती है।

- **साइबर अपराध संपर्क केंद्र (Cyber Crime Contact Centre)**

  बैंक ने C-Edge स्तर पर साइबर क्राइम कॉन्टैक्ट सेंटर को लाइव किया है, जो Cyber Police Portal (CPP) के माध्यम से दर्ज साइबर अपराध संबंधित घटनाओं के प्रबंधन के लिए कार्य करता है। यह केंद्र 24*7 कार्यरत है और बैंक की ओर से वित्तीय साइबर धोखाधड़ी से संबंधित मामलों को संभालता है।

  C-Edge का एजेंट CPP में रिपोर्ट किए गए मामलों का विश्लेषण करता है, CBS में विवरण की पुष्टि कर उचित कार्यवाई प्रारंभ करता है, और संबंधित अद्यतन CPP पोर्टल पर दर्ज करता है। एजेंट की गतिविधियों की दैनिक रिपोर्ट्स (CBS Teller, Set / Remove Hold Report) के माध्यम से निगरानी की जाती है।

Cyber Crime Contact Centre की सुरक्षा व्यवस्था:

- केवल बायोमेट्रिक एक्सेस वाले एजेंट/अधिकृत व्यक्ति को ही प्रवेश की अनुमति होगी।
- मोबाइल फोन, अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण एवं स्मार्ट वॉच अंदर ले जाना वर्जित होगा।
- CCC पूरी तरह पेपरलेस होगा।

IV. डिजिटल परिवर्तन और इंटरऑपरेबिलिटी को अपनाना

- **राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म्स के साथ एकीकरण**

  बैंक अब NPCI के भारत आधार सीडिंग एनेबलर (BASE) प्लेटफॉर्म पर लाइव हो चुका है, जिससे आधार-आधारित सेवाओं को सशक्त रूप से सक्षम किया गया है।

  बैंक ने Account Aggregator API Version 2.0.0 को भी ऑनबोर्ड किया है, जिससे ग्राहकों की सहमति से वित्तीय जानकारी का सुरक्षित और सहज आदान-प्रदान संभव हो सका है।

- **UPI और मोबाइल बैंकिंग में सुधार**

  बैंक ने UPI रिक्करिंग मैंडेट्स (ऑटो पे) को सफलतापूर्वक लागू किया है, जिससे ग्राहक आवर्ती भुगतानों को सुविधाजनक ढंग से सेट कर सकते हैं।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, मोबाइल बैंकिंग के 21,768 और इंटरनेट बैंकिंग के 4,748 नए पंजीकरण हुए, जो हमारे डिजिटल चैनलों की बढ़ती स्वीकृति को दर्शाता है।

AEPS एकीकरण

AEPS (आधार सक्षम भुगतान प्रणाली) को Olive Gateway में सफलतापूर्वक लाइव किया गया है।

आधार के माध्यम से ई-मैंडेट्स

बैंक ने आधार आधारित ई-मैंडेट्स की सुविधा को लाइव किया है।

PAN सत्यापन

PAN सत्यापन को अब Core Banking System (CBS) के साथ एकीकृत कर दिया गया है, जिससे डेटा की शुद्धता और प्रोसेसिंग दक्षता में सुधार हुआ है।

एटीएम विस्तार

बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 87,312 एटीएम कार्ड जारी किए है।

ग्राहक सेवा एवं शिकायतों का निपटान

हम अपने समर्पित कर्मचारियों के माध्यम से सर्वोत्तम ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिये प्रतिबद्ध है। ग्राहकों की शिकायतों का प्रभावी और समय पर निवारण तथा सेवा की गुणवत्ता में सुधार के लिये बैंक बोर्ड द्वारा अनुमोदित शिकायत निवारण नीति का पालन करता है। बैंक ने शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण पर अत्यधिक जोर दिया है तथा निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत शिकायतों को निपटाने के लिये अनुवर्ती प्रणाली को और अधिक मजबूत किया गया है। ग्राहक अपनी शिकायतों को शिकायत प्रकोष्ठ, प्रधान कार्यालय को प्रेषित कर सकते हैं तथा हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी लिख सकते हैं। क्षेत्रीय कार्यालयों व प्रधान कार्यालय का पता और सम्पर्क विवरण हमारी सभी शाखाओं पर उपलब्ध है। सभी शाखाएं प्रत्येक तिमाही में ग्राहक गोष्ठी का आयोजन कर रही हैं। ग्राहक हमारी वेबसाइट का उपयोग कर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। महाप्रबन्धक को बैंकिंग लोकपाल के माध्यम से प्राप्त शिकायतों हेतु नोडल अधिकारी के रुप में नामित किया गया है।

सूचना का अधिकार अधिनियम

भारत सरकार के निर्देशों के अनुपालन में बैंक के विभिन्न पदाधिकारियों के कार्य में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिये बैंक द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 लागू किया गया है।

शाखा स्तर पर शाखा प्रबन्धक को केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी (CAPIO) के रुप में नामित किया गया है तथा सम्बंधित क्षेत्रीय प्रबन्धक को केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (CPIO) बनाया गया है। प्रधान कार्यालय स्तर पर वरिष्ठ प्रबन्धक (मा. संसा.) केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी तथा मुख्यप्रबन्धक (डीपीडी) को केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी बनाया गया है। बैंक में महाप्रबन्धक (प्रशासन) सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अपीलीय अधिकारी नामित हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत वर्ष 2024-25 के दौरान बैंक द्वारा 132 आवेदन और 28 अपील प्राप्त हुई हैं तथा 129 आरटीआई और 27 अपील निर्धारित समय सीमा के भीतर निस्तारित कर दी गई। शेष 3 आरटीआई आवेदन और 1 आरटीआई अपील का निस्तारण नियत समय पर किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, बैंक ने 5 केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) और 1 उत्तराखण्ड राज्य सूचना आयोग (UIC) की सुनवाई में भाग लिया।

स्वप्रेरित पारदर्शिता ऑडिट (Suo-Moto transparency audit) पहली बार दिनांक 25.05.2024 को तृतीय पक्ष के माध्यम से किया गया।

सतर्कता प्रशासन

सिस्टम को मजबूत करने के लिए बैंक ने कर्मचारियों के साथ सभी बैठकों में व्हिसल ब्लोअर नीति पर बार-बार जोर दिया है। इसके अलावा, जीएम (सतर्कता) नियमित अंतराल पर शाखाओं का दौरा करते हैं और दौरे के दौरान कर्मचारियों के बीच जागरूकता लाने के लिए शाखाओं को अवगत किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान क्षेत्रीय कार्यालयों एवं प्रधान कार्यालय में कुल 28 पीवीसी बैठकें आयोजित की गई।

यूजीबीएलसी में वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 733 प्रतिभागियों के साथ कुल 29 ऑफलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम कर्मचारियों को सतर्कता के बारे में जागरूक करने और दैनिक कार्यों में आवश्यक सावधानियां बरतने हेतु आयोजित किए जा रहे हैं।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में महाप्रबंधक (सतर्कता) द्वारा 40 शाखाओं की स्वप्रेरित (Suo-Moto) जांच की गई, जिनमें से 31 स्वप्रेरित अनुपालन रिपोर्ट दिनांक 31.03.2025 तक बंद कर दी गई हैं।

सतर्कता विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में बैंक के लिए सतर्कता पुस्तिका तैयार की गई।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह

बैंक ने प्रधान कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों और सभी शाखाओं में 28.10.2024 से 03.11.2024 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया है। कई शाखाओं ने सप्ताह के दौरान स्कूलों और ग्राम सभाओं में कार्यशालाओं का आयोजन किया। बैंक ने जागरूकता सप्ताह के दौरान सभी कर्मचारियों के लिए एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का भी आयोजन किया।

स्टाफ के द्वारा अखंडता प्रतिज्ञा ली गई।

मानव संसाधन प्रबंधन

दिनांक 31.03.2025 को कर्मचारियों की संख्या (मार्च 2024 में सेवानिवृत्ति/त्यागपत्र के आधार पर बैंक सेवा से विरत् कर्मचारियों को छोड़कर) निम्नवत है:

पदनाम	कुल सं.	महिला	सामान्य	अनु. जा.	अनु. जनजा.	अ. पि.जा.
अधिकारी श्रेणी V	5	0	5	0	0	0
अधिकारी श्रेणी IV	15	1	11	2	0	2
अधिकारी श्रेणी III	55	5	37	9	4	5
अधिकारी श्रेणी II	199	36	124	30	15	30
अधिकारी श्रेणी I	386	113	212	71	25	78
कार्यालय सहायक	340	93	211	67	12	50
कार्यालय परिचर	20	6	16	3	0	1
कुल	**1020**	**254**	**611**	**182**	**56**	**166**

वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 67 कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं जिनमें 12 स्वैच्छिक सेवानिवृत्त कर्मचारी भी शामिल है। 33 कर्मचारियों के द्वारा त्यागपत्र दिया गया है तथा 1 कर्मचारी की वर्ष के दौरान मृत्यु हो गई है।

भर्तियाँ

दिनांक 31.03.2024 को बैंक व्यवसाय के आधार पर बैंक द्वारा विभिन्न ग्रेडों में कर्मचारियों की भर्ती की गयी है जिसमें सामान्य बैंकिग के साथ साथ विशेषज्ञता वाले स्केल द्वितीय व स्केल तृतीय अधिकारियों की पार्श्व भर्ती शामिल है।

ग्रेड	वर्ष के दौरान भर्तियों की संख्या
कार्यालय परिचर	00
कार्यालय सहायक	71
अधिकारी श्रेणी I	38
अधिकारी श्रेणी II	07
अधिकारी श्रेणी III	00

सभी नियुक्तियां आईबीपीएस द्वारा संचालित लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार द्वारा सम्पन्न की गयी हैं।

पदोन्नतियां

कर्मचारियों को त्वरित पदोन्नति देने की बैंक की नीति को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा दिनांक 31.03.2024 के व्यवसाय एवं जनशक्ति आकलन के आधार पर पदोन्नतियाँ की गई हैं और विभिन्न संवर्गो में 105 लोगों को अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नत किया गया:

S.No.	Promoted to	No. of Posts
1	अधिकारी श्रेणी - V	02
2	अधिकारी श्रेणी - IV	04
3	अधिकारी श्रेणी - III	16
4	अधिकारी श्रेणी - II	31
5	अधिकारी श्रेणी - I	52
6	कार्यालय सहायक	00
	Total	**105**

बैंक ने अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के पदोन्नति हेतु योग्य उम्मीदवारों को पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण देने की वैधानिक आवश्यकता को पूरा किया है, ऐसे कार्मिकों को लिखित परीक्षा से पूर्व प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रकार अनु. जाति/अनु. जनजाति के उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा में भाग लेने से पूर्व बेहतर तैयारी करनें में सक्षम बनाया है।

प्रशिक्षण-स्टाफ प्रशिक्षण केन्द्र

वर्ष के दौरान बैंक ने 48 (ऑनलाइन एवं ऑफलाइन) प्रशिक्षण (कार्यक्रम आयोजित किये जिनमें 785 स्टाफ सदस्यों (पुनरावर्तकों) सहित को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। प्रतिभागियों में सभी संवर्ग शामिल है (अधिकारी -600, कार्यालय सहायक और कार्यालय परिचर -185)

150 अधिकारियों ने नाबार्ड/बर्ड (मंगलुरु और लखनऊ), आरबीआई (सीएबी, पुणे), एसबीआईआरबी (हैदराबाद), जैसे बाहरी प्रशिक्षण संस्थानों से केवाईसी-एएमएल, एएलएम, आरटीआई अधिनियम, ट्रेजरी प्रबंधन, व्यवसाय विकास ऋण मूल्यांकन, अनुपालन, एनपीए प्रबंधन आदि पर 20 अश्वफलाइन और ऑनलाइन प्रशिक्षण सत्रों में भाग लिया। बैंक की प्रशिक्षण नीति के अनुसार वित्तीय वर्ष के लिए कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए समग्र लक्ष्य प्राप्त किए गए थे।

बैंक के इन हाउस लर्निंग सेन्टर में नव नियुक्त कार्मिकों को प्रशिक्षण देने और उन्हें पुनः प्रशिक्षित करने व सभी क्षेत्रों में दक्ष करने के लिये लगातार काम किया जा रहा है ताकि उन्हें दैनिक कार्यो के सफल संचालन के लिये कुशल बनाया जा सके।

बैंक महिला कर्मचारियों के हितों पर निरन्तर ध्यान दे रही है। वे कुल कार्यबल का लगभग 25 प्रतिशत हैं। बैंक ने संस्था के भीतर सशक्तिकरण को वढावा देने के लिये कई कदम उठाये हैं। वर्ष के दौरान 175 महिला कर्मचारियों को विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए समिति और आंतरिक शिकायत समिति

बैंक कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों को लागू करके बैंक में महिला कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित कामकाजी माहौल भी बनाया है। हमने सभी 5 क्षेत्रीय कार्यालयों में आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया है। और प्रधान कार्यालय में महिला कर्मचारियों के यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए यौन उत्पीड़न की शिकायतों को संभालने और आरओ स्तर पर हल की गई यौन उत्पीड़न की शिकायतों की समीक्षा करने के लिए समिति गठित की गई है। हम दोनों लिंगों के कर्मचारियों को स्वस्थ और अनुकूल कार्य वातावरण को बढ़ावा देने के लिए जागरूक कर रहे हैं।

कर्मचारी कल्याण के उपाय

मेडिक्लेम पालिसी

भारत सरकार के पत्र संख्या F81/2015-RRB दिनांक 20.10.2016 के संदर्भ में बैंक द्वारा दसवें एवं ग्यारहवें द्विपक्षीय वेतन समझौते की शर्तों के अनुसार अधिकारियों व कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों हेतु चिकित्सा बीमा योजना लागू की गयी है। इस योजना में कर्मचारी + पति या पत्नी + आश्रित बच्चे + 02 आश्रित माता पिता/सास-ससुर हेतु क्रमशः अधिकारियों व कर्मचारियों के लिये क्रमशः ₹ 4 लाख व ₹ 3 लाख का चिकित्सा बीमा उपलब्ध है। आकस्मिक चिकित्सीय खर्चो के लिए ₹ 20 लाख का बफर कोटा रखा गया है। इस योजना में अस्पताल में परेशानी मुक्त तुरन्त भर्ती की सुविधा और कैशलेस चिकित्सा सुविधा के द्वारा अस्पताल भर्ती दावों के निपटान को बहुत आसान बना दिया गया है, जिससे प्रशासनिक समय की काफी बचत होती है। इस योजना में बीमा राशि का 10 प्रतिशत तक बगैर भर्ती हुए घर पर रहकर उपचार में हुए व्यय भी शामिल है।

सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी

कर्मचारियों के बीच सुरक्षा की भावना पैदा करने और संस्थान के प्रति वफादारी का निर्माण करने के लिये निम्नलिखित बीमा राशि के साथ सभी कर्मचारी सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पालिसी के अंर्तगत आच्छादित हैं।

क्रमांक	पद	बीमित राशि
1	अधिकारी	₹ 60 लाख
2	कार्यालय सहायक	₹ 40 लाख
3	कार्यालय परिचर	₹ 30 लाख

सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पॉलिसी (कोविड-19)

महामारी कोविड-19 के कठिन समय के दौरान कर्मचारियों के बीच सुरक्षा की भावना पैदा करने और संस्थान के प्रति निष्ठा का निर्माण करने के लिये निम्नलिखित बीमा राशि के साथ सभी कर्मचारी सामूहिक व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा पालिसी के अंर्तगत आच्छादित हैं।

क्रमांक	पद	बीमित राशि
1	अधिकारी	₹ 20 लाख
2	कार्यालय सहायक	₹ 10 लाख
3	कार्यालय परिचर	₹ 10 लाख

ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण फंड

बैंक द्वारा ग्रेच्युटी की अनुमानित आवश्यकता हेतु आवश्यक प्रबन्ध किये हैं। बैंक को 31.03.2025 में ₹ 48.66 करोड़ ग्रेच्युटी हेतु व ₹ 42.30 करोड़ अवकाश नकदीकरण हेतु कुल कॉर्पस है।

पेंशन

शासन के निर्देशानुसार भारत सरकार ने सभी पात्र कर्मचारियों के लिए उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक कर्मचारी पेंशन विनियमन 2018 के माध्यम से अपने बैंक में पेंशन लागू की है। वर्तमान में, हम 365 सामान्य पेंशनभोगियों और 87 पारिवारिक पेंशनभोगियों को पेंशन वितरित कर रहे हैं। बैंक ने दिनांक 01.11.1993 से कुल 44 नियमित और 60 पारिवारिक पेंशनधारकों को पेंशन एरियर के रूप में ₹ 7.13 करोड़ (जिसमें ₹ 1.92 करोड़ चार स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति, एक सेवा से बर्खास्तगी एवं एक अनिवार्य सेवानिवृत्ति मामले शामिल हैं) का भुगतान किया है।

बैंक ने अपने पेंशनधारकों को ₹ 5.03 करोड़ की राशि के समतुल्य समर्पण एरियर, अनुग्रह राशि एरियर, 12वीं द्विपक्षीय समझौता एरियर एवं स्टैगनेशन एरियर का भी भुगतान किया है।

बैंक द्वारा अपने पेंशनधारकों एवं पारिवारिक पेंशनधारकों के लिए पहचान पत्र सुविधा भी प्रारंभ की गई है।

औद्योगिक संबंध

प्रबंधन तन्त्र, अधिकारी संगठन व कर्मचारी संघ द्वारा स्टाफ सदस्यों के कल्याण तथा व्यवसाय वृद्धि के लिये मिलकर काम किया गया है। वर्ष के दौरान उत्पन्न हुये मुद्दों को सौहार्दपूर्ण समाधान द्वारा निस्तारित किया गया है। वर्ष के दौरान सहयोगपूर्ण व सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहा।

अनुसूचित जाति/जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों का कल्याण

बैंक द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति के साथ सौहार्दपूर्ण सम्बंध बनाये रखा गया है और भर्तियों व पदोन्नति आदि के सभी पहलुओं में सभी वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया गया है। बैंक द्वारा शिकायतों के निवारण के लिये कल्याण संघों के प्रतिनिधियों एवं उनके जन सम्पर्क अधिकारियों के साथ नियमित बैठकें की गई हैं।

बैंक द्वारा कर्मचारियों के मनोबल और उत्साह को बनाये रखने के लिये सभी कदम उठाए हैं।

सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान

बैंक द्वारा सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान सेवानिवृत्ति तिथि को ही कर दिया जाता है। सेवानिवृत्ति की तिथि को भुगतान करने के लिये सभी औपचारिकताऐं पूरी करने के लिये सेवानिवृत्ति से तीन माह पूर्व ही प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जाती है।

एक्सग्रेसिया का भुगतान

बैंक द्वारा भारत सरकार के अधिसूचना संख्या F.20/5/2003-RRB दिनांक 09.06.2006 में दिये गये निर्देशों का पालन किया गया है, जिसमें मृतक व गम्भीर रोग से पीड़ित कर्मचारियों के कानूनी उत्तराधिकारियों को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के स्थान पर एक्सग्रेसिया का भुगतान किया जाता है।

अनुकम्पा नियुक्ति

बैंक ने 06.03.2019 को भारत सरकार के निर्देश के अनुसार आरआरबी में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित मॉडल योजना लागू की है, जो उनकी अधिसूचना संख्या: एफ.एन.ओ. 7/38/2014-आरआरबी दिनांक 31.12.2018 में निहित है।

वित्तीय वर्ष 2023-24 में डीएफएस आदेश क्रमांक एफ.एनओ. 11/19/2023-दि.14.09.2023 बैंक ने 06.03.2014 से भारत सरकार के निर्देशानुसार आरआरबी में अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित संशोधित मॉडल योजना लागू की है। बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में 16 आवेदकों को अनुकम्पा नियुक्ति दी गई है।

कर्मचारी शिकायत निवारण प्रणाली

बैंक द्वारा प्रधान कार्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण करने के लिये कर्मचारी शिकायत निवारण समिति का गठन किया है। वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

कर्मचारी सहभागिता

बैंक अपने ज्ञान संसाधनों को प्रोत्साहित करने और उन्हें सक्रिय रूप से जोड़ने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है, जैसे कि मासिक आधार पर ''वॉल ऑफ फेम'', क्रिकेट टूर्नामेंट, दिवाली उत्सव, होली उत्सव, महिला दिवस आदि का आयोजन।

इसके अतिरिक्त, बैंक ने ''नॉलेज बूस्टर'' नामक एक ऑनलाइन क्विज की शुरुआत की है, जो हर पांच दिन में एचआरएमएस पर आयोजित

की जाती है, ताकि कर्मचारियों को विभिन्न बैंकिंग विषयों की जानकारी अद्यतन रूप से मिलती रहे।

पर्यावरण, सामाजिक और शासन (ईएसजी) सर्वोत्तम कार्यप्रणालियाँ

यूजीबी स्थिरता, सामाजिक जिम्मेदारी और अच्छे कॉर्पोरेट प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए अपनी व्यावसायिक रणनीतियों और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में ईएसजी कारकों को एकीकृत करने के लिए प्रतिबद्ध है।

पर्यावरण संबंधी जिम्मेदारी

बैंक ऊर्जा की खपत को कम करने, कागज के उपयोग को कम करने और हरित प्रौद्योगिकियों को अपनाने के माध्यम से स्थायी प्रथाओं को लागू करके अपने पर्यावरण पदचिह्न को कम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बैंक ने चालू वित्त वर्ष में उत्तराखण्ड के "हरेला" त्यौहार पर 294 पेड़ लगाए हैं।

हमने अक्टूबर 2024 के पहले सप्ताह में एक स्वच्छता अभियान चलाया और तुंगनाथ, विश्व का सर्वोच्च शिव मंदिर, लक्ष्मण सिद्ध मंदिर आदि जैसे विरासत स्थलों की सफाई की।

इसके अतिरिक्त, बैंक ने सतत बुनियादी ढांचे के विकास के लिए लगभग 75 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजनाओं को वित्तपोषित किया है।

सामाजिक योगदान

सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के तहत, बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन अपने प्रधान कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों तथा विभिन्न शाखाओं में किया, जिससे कर्मचारियों और समुदाय में स्वस्थ शरीर व मस्तिष्क को अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिला।

इसके अतिरिक्त, बैंक ने जरूरतमंदों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण कर सामाजिक कल्याण गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी निभाई, जिससे समुदाय सेवा और जनकल्याण के प्रति अपनी निष्ठा को पुनः स्थापित किया।

कॉर्पोरेट शासन प्रणाली

अच्छा कॉर्पोरेट प्रशासन पारदर्शी नियम और नियंत्रण बनाता है, नेतृत्व का मार्गदर्शन करता है, और शेयरधारकों, निदेशकों, प्रबंधन और कर्मचारियों के हितों को संरेखित करता है। बैंक अपने हितधारकों के प्रति पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन को पारदर्शी बनाने में विश्वास करता है।

निदेशक मण्डल की संरचना

निदेशक मण्डल का गठन उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष की अध्यक्षता में किया गया है जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नामित एक प्रतिनिधि, नाबार्ड द्वारा नामित एक प्रतिनिधि, प्रायोजक बैंक, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा नामित दो प्रतिनिधि, राज्य सरकार द्वारा नामित दो प्रतिनिधि तथा भारत सरकार द्वारा नामित दो प्रतिनिधि होते है। दिनांक 31.03.2025 तक कुल नौ निदेशकों में से दो गैर सरकारी निदेशक भारत सरकार द्वारा नामित नहीं किये गये हैं। कलैण्डर वर्ष के दौरान अधिकारियों के स्थानांतरण/सेवानिवृत्ति के कारण संरचना में निम्नलिखित परिवर्तन हुए है। बैंक निवर्तमान निदेशकों के मार्गदर्शन के लिये धन्यवाद व्यक्त करता है एवं नये निदेशकों का स्वागत करता है।

पूर्व निदेशक	नव नियुक्त निदेशक
श्री अमरेन्द्र कुमार सुमन डीजीएम (बीएण्डओ) भारतीय स्टेट बैंक, प्रशासनिक कार्यालय-3, न्यू कैण्ट रोड देहरादून	श्री विनोद कुमार डीजीएम (बीएण्डओ) भारतीय स्टेट बैंक, प्रशासनिक कार्यालय-3,न्यू कैण्ट रोड देहरादून
श्री आनंद स्वरूप अपर सचिव (ग्राम्य विकास) उत्तराखण्ड सरकार	श्री सवीन बंसल अपर सचिव (ग्राम्य विकास) उत्तराखण्ड सरकार
श्री सवीन बंसल अपर सचिव (ग्राम्य विकास) उत्तराखण्ड सरकार	श्री धीरज सिंह गर्ब्याल अपर सचिव (ग्राम्य विकास) उत्तराखण्ड सरकार
श्री धीरज सिंह गर्ब्याल अपर सचिव (ग्राम्य विकास) उत्तराखण्ड सरकार	श्रीमती अनुराधा पाल अपर सचिव (ग्राम्य विकास) उत्तराखण्ड सरकार

दिनांक 31.03.2025 को बोर्ड के निदेशकों का सक्षिप्त विवरण

नाम	पदनाम	योग्यता
श्री हरि हर पटनायक	अध्यक्ष उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक	बी.एससी., एमबीए (बैंकिग व फाइनेन्स)
श्री राजीव कुमार वर्मा	उपमहाप्रबंधक (HR&Ops) भारतीय स्टेट बैंक कार्पोरेट आफिस, मुम्बई	बीएससी
श्री विनोद कुमार	उपमहाप्रबंधक (बीएण्डओ) भारतीय स्टेट बैंक, प्रशासनिक कार्यालय-3, न्यू कैण्ट रोड देहरादून	बी.ए डेटा बेस प्रबंधन में डिप्लोमा व्यावसायिक वित्त में डिप्लोमा
श्री अभय गुप्ता	सहायक महाप्रबंधक भारतीय रिजर्व बैंक, देहरादून	एमबीए
श्री निर्मल कुमार	उपमहाप्रबंधक नाबार्ड, देहरादून	एम.ए. (अर्थशास्त्र) एम.ए. (भूगोल)
सुश्री अनुराधा पाल	अपर सचिव (ग्राम्य विकास) उत्तराखण्ड सरकार	बी.टेक.
श्री गंगा प्रसाद	अपर सचिव (वित्त) उत्तराखण्ड सरकार	एमएससी

निदेशक मण्डल की बैठक

निदेशक मण्डल की बैठक के नियमों के अनुसार एक कैलेण्डर वर्ष में न्यूनतम छः बैठकों का आयोजन किया जाता है तथा त्रैमास में न्यूनतम एक बैठक आयोजित की जाती है। भारत सरकार के राजपत्र में निहित निर्देशों का अनुपालन करते हुए उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक के निदेशक मण्डल द्वारा कैलेण्डर वर्ष 2024 के दौरान कुल 06 बैठकें आयोजित की गयी।

आयोजित बैठकों की संख्या	06					
बैठकों की तिथि	22.03.2024	30.04.2024	27.06.2024	12.07.2024	24.10.2024	10.12.2024

वर्ष 2024 के दौरान निदेशक मण्डल की बैठकों में निदेशको की उपस्थिति इस प्रकार रही।

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	वर्ष के दौरान कुल बैठकें	प्रतिभाग की गयी कुल बैठकें
1	श्री हरि हर पटनायक	अध्यक्ष उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक	6	6
2	श्री अमरेन्द्र कुमार सुमन	उपमहाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक	3	1
3	श्री विनोद कुमार	उपमहाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक	3	3
4	श्री राजीव कुमार वर्मा	उपमहाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक	6	5
5	श्री अभय गुप्ता	सहायक महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक	6	5
6	श्री निर्मल कुमार	उपमहाप्रबंधक, नाबार्ड	6	6
7	श्री गंगा प्रसाद	अपर सचिव (वित्त) उत्तराखण्ड सरकार	6	5
8	श्री आनन्द स्वरूप	अपर सचिव (ग्राम्य विकास) उत्तराखण्ड सरकार	1	1
9	श्री सवीन बंसल	अपर सचिव (ग्राम्य विकास) उत्तराखण्ड सरकार	4	2
10	श्री धीरज सिंह गब्रियाल	अपर सचिव (ग्राम्य विकास) उत्तराखण्ड सरकार	1	0

लेखा परीक्षा समिति

आंतरिक पर्यवेक्षी प्रणाली की निगरानी के लिये दिनांक 19.12.2012 को आयोजित पहली बोर्ड बैठक लेखा परीक्षा समिति का गठन किया गया था, जो नियामक/पर्यवेक्षी संस्थानों को दी गयी सूचना की शुद्धता सुनिश्चित करती है। लेखा परीक्षा समिति के पांच सदस्य हैं और लेखा परीक्षा समिति की चार बैठकें कैलेण्डर वर्ष 2024 में आयोजित की गयी।

आयोजित बैठकों की संख्या	04			
बैठकों की तिथि	22.03.2024	27.06.2024	03.09.2024	28.11.2024

वर्ष 2024 के दौरान निदेशक मण्डल की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति इस प्रकार रही।

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	वर्ष के दौरान कुल बैठकें	प्रतिभाग की गयी कुल बैठकें
1	श्री राजीव कुमार वर्मा	उपमहाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक	4	3
2	श्री अमरेन्द्र कुमार सुमन	उपमहाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक	1	0
3	श्री विनोद कुमार	उपमहाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक	3	3
4	श्री अभय गुप्ता	सहायक महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक	4	4
5	श्री निर्मल कुमार	उपमहाप्रबंधक, नाबार्ड	4	4
6	श्री गंगा प्रसाद	अपर सचिव (वित्त, उत्तराखण्ड सरकार)	4	4

धोखाधड़ी निगरानी समिति

धोखाधड़ी निगरानी समिति का मुख्य कार्य धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन के लिये आंतरिक नीति को तैयार करना है। दिनांक 19.12.2012 को पहली बोर्ड बैठक में फ्राड मानिटरिंग कमेटी का भी गठन किया गया था, इसके पांच सदस्य हैं।

वर्ष के दौरान कुल बैठकें	04			
बैठकों की तिथि	22.03.2024	27.06.2024	03.09.2024	28.11.2024

वर्ष 2024 के दौरान निदेशक मण्डल की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति इस प्रकार रही।

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	वर्ष के दौरान कुल बैठकें	प्रतिभाग की गयी कुल बैठकें
1	श्री हरि हर पटनायक	अध्यक्ष उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक	4	4
2	श्री राजीव कुमार वर्मा	उपमहाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक	4	3
3	श्री अमरेन्द्र कुमार सुमन	उपमहाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक	1	0
4	श्री विनोद कुमार	उपमहाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक	3	3
5	श्री आनन्द स्वरूप	अपर सचिव (ग्राम्य विकास) उत्तराखण्ड सरकार	1	1
6	श्री सवीन बंसल	अपर सचिव (ग्राम्य विकास) उत्तराखण्ड सरकार	2	2
7	श्री धीरज सिंह गब्रियाल	अपर सचिव (ग्राम्य विकास) उत्तराखण्ड सरकार	1	1
8	श्री गंगा प्रसाद	अपर सचिव (वित्त) उत्तराखण्ड सरकार	4	4

20 लाख रुपये से अधिक की धोखाधड़ी के लिए धोखाधड़ी निगरानी समिति

नाबार्ड परिपत्र संख्या NB-DoS-CFMC/2927/P&80/ 2016-17 दिनांक 06.12.2016 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, 20 लाख रुपये और उससे अधिक की धोखाधड़ी की निगरानी समिति का गठन बोर्ड की बैठक दिनांक 19.10.2020 में किया गया था, इसके पांच सदस्य हैं।

वर्ष के दौरान कुल बैठकें	04			
बैठकों की तिथि	22.03.2024	27.06.2024	03.09.2024	28.11.2024

वर्ष 2024 के दौरान निदेशक मण्डल की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति इस प्रकार रही।

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	वर्ष के दौरान कुल बैठकें	प्रतिभाग की गयी कुल बैठकें
1	श्री हरि हर पटनायक	अध्यक्ष उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक	4	4
2	श्री राजीव कुमार वर्मा	उपमहाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक	4	3
3	श्री अमरेन्द्र कुमार सुमन	उपमहाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक	1	0
4	श्री विनोद कुमार	उपमहाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक	3	3
5	श्री अभय गुप्ता	सहायक महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक	4	4
6	श्री गंगा प्रसाद	अपर सचिव (वित्त) उराखण्ड सरकार	4	4

ग्राहक सेवा समिति

आरबीआई के परिपत्र संख्या आरबीआई/2015-16/59 डीबीआर नंबर लेग.बीसी.21/09.07.006/2015-16 दिनांक 01.07.2015 द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, ग्राहक सेवा समिति का गठन दिनांक 22.03.2021 को बोर्ड की बैठक में किया गया था और इसके चार सदस्य हैं।

वर्ष के दौरान कुल बैठकें	04			
बैठकों की तिथि	22.03.2024	27.06.2024	03.09.2024	28.11.2024

वर्ष 2024 के दौरान निदेशक मण्डल की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति इस प्रकार रही।

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	वर्ष के दौरान कुल बैठकें	प्रतिभाग की गयी कुल बैठकें
1	श्री हरि हर पटनायक	अध्यक्ष उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक	4	4
2	श्री अमरेन्द्र कुमार सुमन	उपमहाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक	1	0
3	श्री विनोद कुमार	उपमहाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक	3	3
4	श्री अभय गुप्ता	सहायक महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक	4	4
5	श्री निर्मल कुमार	उपमहाप्रबंधक, नाबार्ड	4	4

जोखिम प्रबंधन समिति

दिनांक 22.03.2021 को बोर्ड की बैठक में बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया और इसमें चार सदस्य हैं।

वर्ष के दौरान कुल बैठकें	04			
बैठकों की तिथि	22.03.2024	27.06.2024	03.09.2024	28.11.2024

वर्ष 2024 के दौरान निदेशक मण्डल की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति इस प्रकार रही।

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	वर्ष के दौरान कुल बैठकें	प्रतिभाग की गयी कुल बैठकें
1	श्री हरि हर पटनायक	अध्यक्ष उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक	4	4
2	श्री राजीव कुमार वर्मा	उपमहाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक	4	3
3	श्री अमरेन्द्र कुमार सुमन	उपमहाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक	1	0
4	श्री विनोद कुमार	उपमहाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक	3	3
5	श्री निर्मल कुमार	उपमहाप्रबंधक, नाबार्ड	4	4

एनपीए निगरानी समिति

गैर निष्पादित आस्तियों की निगरानी के लिये दिनांक 29.08.2016 को आयोजित की 25वीं बोर्ड बैठक में तीन सदस्यों वाली एनपीए निगरानी समिति का गठन किया गया था।

वर्ष के दौरान कुल बैठकें	04			
बैठकों की तिथि	22.03.2024	27.06.2024	03.09.2024	28.11.2024

वर्ष 2023 के दौरान निदेशक मण्डल की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति इस प्रकार रही।

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	वर्ष के दौरान कुल बैठकें	प्रतिभाग की गयी कुल बैठकें
1	श्री हरि हर पटनायक	अध्यक्ष उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक	4	4
2	श्री राजीव कुमार वर्मा	उपमहाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक	4	3
3	श्री निर्मल कुमार	उपमहाप्रबंधक, नाबार्ड	4	4

विशेष पुनरीक्षण समिति

कर्मचारियों की सेवा का पुनरीक्षण करने के लिए 72वीं बोर्ड बैठक, जो कि दिनांक 01.11.2023 को आयोजित की गयी थी, में तीन सदस्यीय विशेष पुनरीक्षण समिति का गठन किया गया।

वर्ष के दौरान कुल बैठकें	04			
बैठकों की तिथि	22.03.2024	27.06.2024	03.09.2024	28.11.2024

वर्ष 2024 के दौरान निदेशक मण्डल की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति इस प्रकार रही।

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	वर्ष के दौरान कुल बैठकें	प्रतिभाग की गयी कुल बैठकें
1	श्री हरि हर पटनायक	अध्यक्ष उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक	4	4
2	श्री राजीव कुमार वर्मा	उपमहाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक	4	3
3	श्री निर्मल कुमार	उपमहाप्रबंधक, नाबार्ड	4	4

आईटी उपसमिति

आईटी उपसमिति, जिसमें चार सदस्य शामिल हैं, को क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (आरआरबी) के लिए साइबर सुरक्षा ढांचे की निगरानी हेतु 27.06.2024 को आयोजित 76वीं निदेशक मंडल की बैठक में गठित किया गया।

वर्ष के दौरान कुल बैठकें	02	
बैठकों की तिथि	03.09.2024	28.11.2024

वर्ष 2024 के दौरान निदेशक मण्डल की बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति इस प्रकार रही।

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम	वर्ष के दौरान कुल बैठकें	प्रतिभाग की गयी कुल बैठकें
1	श्री हरि हर पटनायक	अध्यक्ष उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक	2	2
2	श्री राजीव कुमार वर्मा	उपमहाप्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक	2	1
3	श्री निर्मल कुमार	उपमहाप्रबंधक, नाबार्ड	2	2
4	श्री अभय गुप्ता	सहायक महाप्रबंधक, भारतीय रिजर्व बैंक	2	2

संचार के माध्यम

बैंक अपने सभी हितधारकों को पूर्ण एवं प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने में विश्वास रखता है। बैंक हिन्दी व अंग्रेजी में दो प्रमुख समाचार पत्रों में अपना वार्षिक विवरण प्रकाशित कर रहा है। बैंक का वित्तीय विवरण बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है और यह सभी हितधारकों को मुद्रित रुप में प्रदान किया जाता है।

स्वीकृतियाँ (Acknowledgements)

निदेशक मंडल हमारे सभी हितधारकों, साझेदारों एवं ग्राहकों के प्रति गहन आभार व्यक्त करता है, जिनके सहयोग और विश्वास ने हमारी वृद्धि और प्रभाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपकी सहयोग एवं समर्थन हमारी निरंतर सफलता के लिए अमूल्य है।

निदेशक मंडल प्रायोजक बैंक, भारत सरकार, राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक एवं नाबार्ड के प्रति भी अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करते हैं, जिनके मार्गदर्शन, सहयोग और दूरदर्शी रणनीति ने हमारी यात्रा को दिशा देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

बोर्ड, श्री चल्ला श्रीनिवासुलु सेट्टी, अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक, कॉर्पोरेट सेंटर, मुंबई, श्री अश्विनी कुमार तिवारी, प्रबंध निदेशक, एसबीआई, श्री देबांग्शु मुंशी, मुख्य महाप्रबंधक, एसबीआई, कॉर्पोरेट सेंटर, श्री वी. शिवकुमार, महाप्रबंधक (आरआरबी), एसबीआई, कॉर्पोरेट सेंटर एवं एसबीआई, कॉर्पोरेट सेंटर, मुंबई के एएंडएस विभाग के सभी टीम सदस्यों के प्रति गहन कृतज्ञता व्यक्त करता है। उनके दूरदर्शी नेतृत्व, अटूट समर्थन और उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता ने हमारे बैंक को सतत सफलता की ओर अग्रसर करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हम उनके समर्पण, विशेषज्ञता एवं हमारे साझा लक्ष्यों की सतत् प्राप्ति हेतु प्रयासों की सराहना करते हैं।

इसके अतिरिक्त, निदेशक मंडल हमारे सम्मानित ग्राहकों के प्रति भी हार्दिक आभार प्रकट करता है, जिनके निरंतर विश्वास और निष्ठा ने हमें सेवाएं देने का गौरव प्रदान किया है। हम आपके विश्वास पर खरा उतरने और आपकी अपेक्षाओं से भी आगे बढ़ने के लिए पूर्णत: प्रतिबद्ध हैं।

अंतत:, निदेशक मंडल हमारे समर्पित कर्मचारियों के प्रति भी अपनी हार्दिक सराहना व्यक्त करता है। आपका परिश्रम, उत्साह और हमारे मिशन एवं मूल्यों के प्रति निष्ठा ही हमारी सफलता की नींव है। हम आपके योगदान और समर्पण को गहराई से मान्यता देते हैं और उसका उच्च मूल्यांकन करते हैं।

निदेशक मण्डल की ओर से उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक
हरि हर पटनायक
अध्यक्ष

UTTARAKHAND GRAMIN BANK

PERFORMANCE OF THE BANK : AT A GLANCE

(Amount in Thousands)

S.No.	Particulars	31.03.2025	31.03.2024	31.03.2023	31.03.2022	31.03.2021
I	KEY PERFORMANCE INDICATORS					
1	No. of Districts in service area	13	13	13	13	13
2	No. of Branches	291	290	288	286	286
	a) Rural	220	219	217	216	216
	b) Semi-Urban	41	41	41	41	41
	c) Urban	30	30	30	29	29
	d) Metropolitan	0	0	0	0	0
3	Total Staff (Excl. Sponsor Bank Staff)	1020	999	1087	1049	1057
	Out of Which, Officers	660	627	643	613	601
4	Deposits	84704937	78336215	71177595	64855343	60050117
	Growth %	8.13%	10.06%	9.75%	8.00%	9.79%
5	Borrowings	2844105	1909802	1002335	854324	1104273
	Growth %	48.92%	90.54%	17.32%	-22.63%	-11.64%
6	Gross Loans & Advances O/S	45779526	37476356	31473983	27908147	25962925
	Growth %	22.16%	19.07%	12.78%	7.49%	6.94%
	Of 6 above, Loans to Priority Sector	26417579	21337896	18706420	17498102	16677399
	Of 6 above, Loans to SC/ST	3757456	3437340	3219514	3093099	3106364
	Of 6 above, Loans to SF/MF/AL	5160229	4307009	3225956	2968356	3036000
	Of 6 above, Loans to Minorities	1587688	1277169	1093699	1042270	1046099
7	C.D. Ratio	54.05%	47.84%	44.22%	42.96%	43.24%
8	Investment Outstanding (excluding TDRs)	36712501	37224150	34541482	32783267	28994078
	Growth %	-1.37%	7.77%	5.36%	13.07%	15.15%
	i. SLR Investment	35489262	36205109	33795736	32233626	28405478
	ii. Non SLR Investment (excluding TDRs)	1223238	1019041	745746	549641	588600
	CA balances with Bank	329684	501667	321364	316836	284498
	TDR balances with Bank	9055821	8579572	7833889	6803484	7302253
II	AVERAGE					
1	Average Deposits	80475777	73992220	67129865	61675287	57344873
	Growth %	8.76%	10.22%	8.84%	7.55%	11.22%
2	Average Borrowings	2144602	1225169	938763	987152	1162548
	Growth %	75.05%	30.51%	-4.90%	-15.09%	-13.45%

3	Average Gross Loans & Advances O/S	39955015	33307744	28453714	25937773	24474391
	Growth %	19.96%	17.06%	9.70%	5.98%	6.19%
4	Average Investment (excl. TDRs)	36948607	35526696	33665564	31815008	28037448
	Growth %	4.00%	5.53%	5.82%	13.47%	15.76%
	Average SLR Investment	35888060	34590263	33063133	31110752	27099414
	Average Non SLR Investment (excl. TDRs)	1060547	936433	602431	704256	938034
	Average Investment as % to Average Deposits	13.25%	55.44%	50.15%	51.58%	48.89%
5	Average Working Funds	90207230	81379916	72876092	66018286	62158136
III	**LOANS DISBURSED**					
1	Total Loans disbursed during the year	29280537	24684695	20131676	16293456	15147853
	of 1 above, Loans to Priority Sector	15983157	12022893	9235883	7868931	7934742
	of 1 above, Loans to Non-Target Group	13297379	12661802	10895793	8424525	7213111
	of 1 above, Loans to SC/ST	1995044	1887363	1789444	1519253	1362687
	of 1 above, Loans to SF/MF/Agriculture labourers	3953044	3206844	2180811	1688925	1785389
IV	**PRODUCTIVITY**					
1	Per Branch	448400	399354	356429	324726	300745
2	Per Employee	127302	115928	94089	88114	80992
V	**RECOVERY PERFORMANCE**					
1	Total (as on 30th June 2024)					
	Demand	10671788	9819254	8099855	7193591	5530774
	Recovery	9200663	8304407	6554416	5703264	4457172
	Overdues	1471126	1514848	1545439	1490327	1073602
	Recovery %	86.21%	84.57%	80.92%	79.28%	80.59%
(i)	Farm Sector					
	Demand	1786852	1823386	1550027	1653010	1502920
	Recovery	1059511	1118495	870471	1020473	927535
	Overdues	727341	704891	679556	632537	575385
	Recovery %	59.29%	61.34%	56.16%	61.73%	61.72%
(ii)	Non-Farm Sector					
	Demand	8884936	7995868	6549828	5540581	4027854
	Recovery	8141152	7185912	5683945	4682791	3529637
	Overdues	743785	809957	865883	857790	498217
	Recovery %	91.63%	89.87%	86.78%	84.52%	87.63%
VI	**ASSET CLASSIFICATION**					
1	Standard Assets	44290968	35924394	29755053	25896503	23924242
	Sub-Standard Assets	269164	258894	262914	453726	672689
	Doubtful Assets	1185087	1257163	1436496	1545494	1350398
	Loss Assets	34307	35905	19520	12424	15596
	Total Gross Advances	45779526	37476356	31473983	27908147	25962925
2	Standard Asset as % to Gross Advances	96.75%	95.86%	94.54%	92.79%	92.15%

	Gross NPA %	3.25%	4.14%	5.46%	7.21%	7.85%
	Net NPA %	0.00%	0.02%	1.50%	3.04%	3.79%
VII	**PROFITABILITY ANALYSIS**					
1	Interest Paid					
	On Deposits	3483358	3108918	2575741	2391588	2475073
	On Borrowings	140037	71153	43198	44472	54312
2	Salary & Allowances to Employees	1823311	1686027	1360642	1460429	1096744
3	Pension Payment & Provision	177342	50161	653242	666621	680000
4	Other Operating Expenses	808146	650299	664724	577011	526088
5	Provisions made during the Year					
	Against NPAs	8111	253	167441	110072	226969
	Other Provisions	91844	328057	54134	59749	-1035
6	Interest earned					
	On Loans & Advances	3727747	3164460	2736771	2380444	2275071
	On TDRs with Banks	704758	614325	430977	286252	438083
	On SLR Investments	2630974	2547602	2402146	2270817	2001478
	On Non-SLR Investments	62581	59276	45619	41338	61799
7	Misc. Income	445985	386447	343114	401459	297364
8	Profit/Loss					
	Profit before Tax	1039896	877243	439505	70369	15644
	Profit after Tax	781144	752555	437796	68196	15714
VIII	**OTHER INFORMATION**					
1	Share Capital Deposit Received*	4	4	0	0	0
2	D.I.C.G.C.					
	Claims Settled Cumulative	0	0	0	0	0
	Claims received but pending for adjustment	0	0	0	0	0
	Claims pending with the Corporation	0	0	0	0	0
3	Cumulative Provision					
	Against NPAs	1128532	1162417	1258772	1186766	1084928
	Against other intangible assets	0	0	0	0	0
4	Derecognised income					
	During the year	0	0	0	0	0
	Cumulative	0	0	0	0	0
5	Loans written off during the year					
	No. of A/cs	525	993	1164	67	704
	Amount (excluding notional intt.)	42016	100493	104264	8396	110298
6	Accumulated Losses	0	0	0	0	0
7	Reserves	2982465	2201321	1448766	1010970	942775

* Share application money received from GOI

BOARD OF DIRECTOR'S REPORT 2024-25

We are pleased to present the thirteenth report on the business and operations of the Bank, accompanied by the Audited Statement of Accounts for the financial year ending on March 31, 2025.

Overview of Indian economy

The National Statistical Office (NSO) has estimated India's real GDP growth at 6.5 percent for 2024-25 and 6.5 percent for 2025-26 as per RBI's Monetary Policy Statement from April 7 to 9, 2025. Purchasing Manager Index (PMI) manufacturing remained at 58.1 and PMI services remained above 58.5 for the month of March 2025, reflecting strong demand and sustained expansion of the economy.

Retail Inflation eases to 3.34 percent in March 2025 as per The National Statistical Office (NSO), Ministry of Statistics and Programme Implementation (MoSPI). CPI inflation for the financial year 2025-26 is projected at 4.0 per cent, with Q1 at 3.6 per cent; Q2 at 3.9 per cent; Q3 at 3.8 per cent; and Q4 at 4.4 per cent as per RBI's Monetary Policy Statement from April 7 to 9, 2025.

Higher and stubborn inflation had prompted the RBI to tighten the monetary policy, and it raised the policy rate by 250 bps between May 2022 and February 2023, reaching 6.5 per cent.

- In February 2025, the repo rate was cut by 25 bps to 6.25 per cent followed by another rate cut by 25 bps to 6.0 per cent in April 2025.
- RBI reduced the Cash Reserve Ratio (CRR) of all banks by 50 basis points in two equal tranches of 25 basis points in the month of Dec 2024 to 4.00 per cent.

Uttarakhand Economy

Uttarkhand per capita income is expected at Rs. 2,74,064 with an increase of 11.33% as against India's per capita income of Rs. 2,00,162 with an increase of 8.70%.

The growth rate of Uttarakhand's GSDP is projected to grow at 6.6% in 2024-25, lower than the 7.58% growth estimated for 2023-24. 9.83%, 43.46%, and 46.71% contribution to the state's economy by Primary sector, Secondary and Tertiary sector respectively is expected in 2024-25. (Source: Uttarakhand Govt. Budget 2025-26).

Uttarakhand: The Abode of Natural Splendor and Spirituality

Formed on **9th November 2000** as the **27th state of India**, Uttarakhand was carved from the northern districts of Uttar Pradesh. Strategically located at the foothills of the majestic Himalayas, the state is a treasure trove of natural resources, including glaciers, rivers, dense forests, and snow-capped peaks.

Known as **Dev Bhoomi** (Land of the Gods), Uttarakhand is home to the sacred **Char Dhams - Badrinath, Kedarnath, Gangotri, and Yamunotri** - drawing millions of pilgrims and tourists annually. **Dehradun**, a vibrant city with a rich colonial legacy, serves as the state's capital.

Nature and Culture: The state's pristine landscapes include world-renowned national parks like **Jim Corbett National Park** (India's oldest national park), **Valley of Flowers** (a UNESCO World Heritage Site), and untouched villages that preserve traditional Garhwali and Kumaoni cultures. Rich in biodiversity, Uttarakhand offers breathtaking trekking routes, pilgrimage circuits, yoga retreats, and adventure tourism.

Economic and Strategic Importance

- **Tourism:** Uttarakhand ranks among the top Indian states in domestic and international tourist arrivals in the hill category.
- **Agriculture and Horticulture:** Fertile valleys produce high-value crops, medicinal plants, and organic produce.
- **Hydropower:** With abundant river systems, Uttarakhand is a significant contributor to India's hydroelectric potential.
- **Education Hub:** Home to premier institutions like IIT Roorkee, IIM Kashipur, GB Pant University of Agriculture & Technology, Pantnagar, Forest Research Institute Dehradun, and Doon School, the state boasts a strong educational infrastructure.

Major Infrastructure Projects

- **Delhi–Dehradun Expressway:** 210 km expressway to cut travel time dramatically.
- **Dehradun–Mussoorie Ropeway:** Set to be India's longest ropeway, enhancing hill connectivity.
- **Rishikesh–Karnaprayag Railway Line:** Improving rail access to the interiors of the Garhwal region.
- **Kailash Mansarovar Yatra Route via Pithoragarh:** Providing safer, faster access for pilgrims.
- **Kedarnath Ropeway:** Planned to be the world's highest and longest ropeway at high altitude.

Quality of Life: Uttarakhand offers a peaceful environment with a harmonious blend of traditional values and modern amenities. The state's friendly communities, clean air, spiritual depth, and natural beauty make it a top choice for living, working, and investing.

Overview of Banking Industry in Uttarakhand

There are total 35 Banks in Uttarakhand having 2585 branches as on 31.12.2024. State has total 35 Banks comprising 12 PSBs, 1 RRB (UGB), 15 Private Banks, 5 Small Finance Banks and Co-operative Bank (1 State Cooperative Bank, 10 District Central Co-operative Banks). Besides, there is one branch of Prathama Gramin Bank in Haridwar District.

Total deposits of all the Banks in the state stood at Rs. 230739 crore as on 31.12.2024 at 9.28% YoY growth. Total advances of all the Banks in the State is Rs. 121271 crore (excluding RIDF) as on 31.12.2024 at 9.10% YoY growth. The Gross NPA of all Banks in the State is 3.96% as on 30.09.2023.

CD ratio of the state is 54.01% and the CD ratio excluding RIDF is 52.56% as on 31.12.2024. Agricultural advances contribute 13.55% of total advances and Priority sector advances contribute 49.35% of total advances as on 30.09.2024. MSME advances constitute 26.28% of total advances as on 30.09.2024. (Source: SLBC Book).

New Branch/ Offices

The bank has a presence in all 13 districts of Uttarakhand with a network of 291 branches and 624 Business Correspondents. The bank has opened one new Branch during the FY 2024-25. Details are given below:

Category	Code	Name	Date of opening
Branch	178	Naugaon	25-03-2025

Business Review

The Bank's business has grown at a rate of 12.67% to reach ₹ 13,048.45 crore as on 31 March 2025 as against ₹ 11,581.26 Crore as on 31 March 2024.

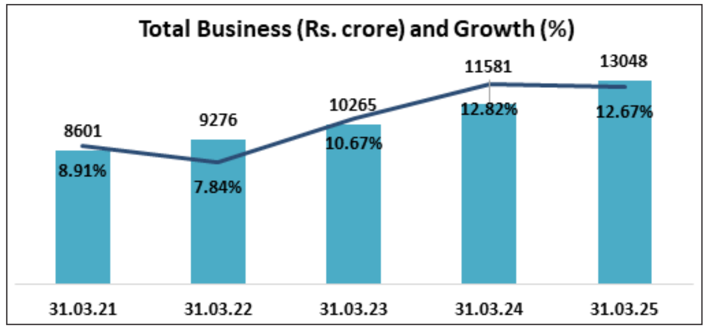

Profit Analysis

The Bank has earned ₹ 113.90 crores operating profit and ₹ 78.11 crores net profit in FY 2024-25 after payment of ₹ 16.53 crores for Computer Increment arrear since 1993, ₹ 8.37 crores for NPS revision (employer share 14% from 11.11.2020) and ₹ 1.47 crores for the gratuity (revised upper limit).

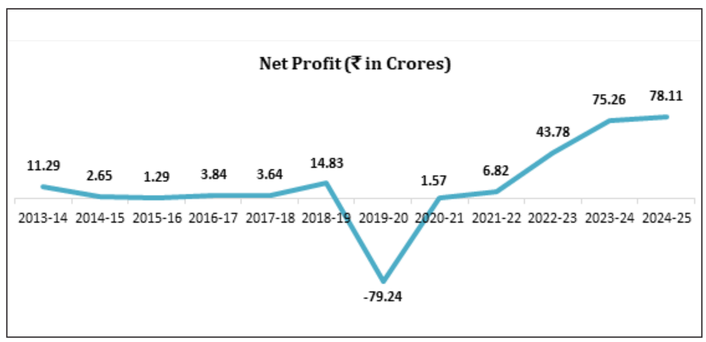

Income and Expenditure

(₹ in Crore)

Particulars	2023-24	2024-25	Growth %
Interest Income	638.57	712.61	11.59%
Interest Expenditure	318.01	362.34	13.94%
Other Income	38.64	44.60	15.42%
Operating Expenses	238.65	280.88	17.70%
Operating profit	120.56	113.99	-5.45%
Provisions and Contingencies	32.83	10.00	-69.54%
Profit before tax	87.73	103.99	18.53%
Income Tax	12.50	25.92	107.36%
Deferred Tax Asset & Earlier year adjustments (excess)	0.03	0.05	66.67%
Net Profit after tax	75.26	78.11	3.79%

Net Interest Income

Total interest income earned during the year is ₹ 712.61 crores whereas total interest expenditure is at ₹ 362.34 crores. The net interest income has increased by ₹ 29.71 crores to ₹ 350.27 crores during the year vis-à-vis ₹ 320.56 crores in 2023-24.

(₹ in Crore)

Interest Expenditure

- Interest paid on deposits has increased to ₹ 348.34 Crore from the last FY's figure of ₹ 310.89 Crore by ₹ 37.45 Crore. Cost of deposits increased by 13 basis points to 4.33% as against 4.20% in 2023-24.
- The average cost of borrowings has increased from 5.81% in 2023-24 to 6.53% in 2024-25. The Bank has paid ₹ 14.00 Crore towards interest on borrowings (refinance from NABARD and other organizations) during the year as against ₹ 7.12 crores during the previous FY.

(₹ in Crore)

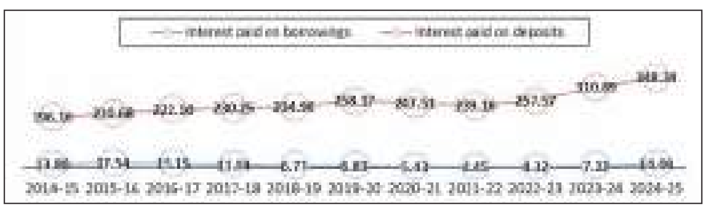

Operating expenditure

- Operating expenditure has increased by ₹ 42.23 Crore (17.70%) to ₹ 280.88 Crore in 2024-25 from ₹ 238.65 Crore in the previous FY 2023-24.
- Operating expenditure also includes ₹ 17.73 crores contribution/provision towards annual pension liability in FY 2024-25 and payment of ₹ 16.53 crores for Computer Increment arrear, ₹ 8.37 crores for NPS revision (employer share 14% from 11.11.2020) and ₹ 1.47 crores for the gratuity (revised upper limit).

Other Income

- Other income increased by ₹ 5.96 crores (15.42%) to ₹ 44.60 crores during 2024-25 from ₹ 38.65 crore during 2023-24. The Bank has earned ₹ 1.96 crore through profit on sale of investment during the FY. Share of non-interest income to total income increased marginally from 5.71% during FY 2023-24 to 5.89% during FY 2024-25.

Interest Income

- Interest income increased from ₹ 638.57 Crore to ₹ 712.61 Crore during the FY 2024-25 with an absolute growth of ₹ 74.04 Crore (@ 11.59%).
- The Bank has earned an interest income of ₹ 372.77 Crore from loans and advances in current fiscal as against ₹ 316.45 Crore in 2023-24 with an increase of ₹ 56.33 Crore (@17.80%).
- The interest income received from investments and term deposits in other Bank has increased by ₹ 17.71 Crore to reach ₹ 339.83 Crore as against ₹ 322.12 Crore in the previous FY.

Provision for NPAs:

- The Bank has made a provision of ₹ 0.81 crore on NPAs and ₹ 2.57 crore for standard assets during FY 2024-25.

(₹ in Crore)

Assets	2023-24		2024-25	
	O/s	Provisions	O/s	Provisions
Standard	3592.44	12.21	4429.10	14.77
Sub-Standard	25.89	4.08	26.92	4.16
Doubtful	125.72	108.57	118.51	105.26
Loss	3.59	3.59	3.43	3.43
Total	**3747.64**	**128.45**	**4577.95**	**127.63**

In addition to the above, Bank has made a floating provision of of ₹ 8.30 crore during FY 2024-25 and ₹ 37.48 crore (1% of total advances as on 31.03.2024) during FY 2023-24 as per RBI guidelines after board approval.

Ratio Analysis

S. No.	Ratios	Units	2023-24 Amt/Ratio	2024-25 Amt / Ratio	Change
1	Yield on advances	%	9.50	9.33	-0.17
2	Yield on investments	%	7.34	7.29	-0.05
3	Cost of deposits	%	4.20	4.33	0.13
4	Cost of borrowings	%	5.81	6.53	0.72
5	Avg. cost of funds	%	4.20	4.30	0.10
6	Avg. return of funds	%	8.43	8.46	0.03
7	Cost of management	%	2.93	3.11	0.18
8	Misc. Income as % to Working Funds	%	0.47	0.49	0.02
9	Net Margin	%	1.08	1.15	0.07
10	Financial Margin	%	4.23	4.16	-0.07
11	Risk Cost	%	0.40	0.11	-0.29
12	Return on Assets	%	0.92	0.87	-0.05
13	Return on Equity	%	18.64	16.21	-2.43
14	Expenses ratio	%	66.44	71.13	4.69
15	Gross NPAs	₹ Crores	155.20	148.86	-6.34
16	Net NPAs	₹ Crores	0.69	0.00	-0.69
17	% Provisions to gross NPAs	%	99.55	100	0.45
18	Gross NPAs to advances	%	4.14	3.25	-0.89
19	Net NPAs to advances	%	0.02	0.00	-0.02
20	CRAR	%	12.64	12.63	-0.01

Balance Sheet Size

The balance sheet size increased from ₹ 8736.95 crores as on 31.03.2024 to ₹ 9546.76 crore as on 31.03.2025 with an increase of ₹ 809.81 crores as compare to ₹ 976.57 Crores increase in the previous year.

Share Capital & Reserves

The total authorized capital of the Bank is ₹ 2,000 crore; divided into 200,00,00,000 fully paid-up equity shares of ₹ 10 each. The total paid-up share capital of the Bank is ₹ 1,84,26,65,000 (18,42,66,500 shares of ₹ 10 each) as on 31.03.2025. Share capital is contributed by the Central Government, State bank of India (Sponsor Bank), and State Government in ratio of 50:35:15 respectively.

(Amount in ₹)

Shareholders	Shareholding %	Total capital as on 31.03.2025
Govt. of India	50%	921,332,500
State Bank of India	35%	644,932,750
Govt. of Uttarakhand	15%	276,399,750
Total		**1,842,665,000**

Net Reserves stood at ₹ 298.25 crores as on 31.03.2025 as against ₹ 220.13 Crores as on 31.03.2024.

CRAR

The Capital Adequacy Ratio marginally reduced to 12.63% at the end of the financial year compared to 12.64% as on 31.03.2024. Details of Tier-I, Tier-II Capital, Reserves and computation of CRAR are given below:

	Capital	2023-24	2024-25
1	**Tier-I**		
	a. Paid up Capital including share capital deposits	184.27	184.27
	Less: Accumulated Losses/Intangible Assets	0.67	0.71
	b. Statutory Reserves & Surplus	68.86	84.48
	c. Capital Reserves	0.00	0.00
	d. Other Reserves	82.10	82.10
	e. Spl. Reserve u/s 36(1)(viii) of Income Tax Act 1961	0.00	0.00
	f. Surplus in P&L	25.66	88.16
	Total reserves (b+c+d+e+f+g)	**176.62**	**254.30**
	Total Tier-I Capital	**360.22**	**438.29**
2	Tier-II		
	a. Undisclosed Reserves	0.00	0.00
	b. Revaluation Reserves	0.00	0.00
	c. General Provisions & Reserves	15.19	26.53
	d. Investment fluctuations Reserves/Fund	43.51	43.51
	Total Tier-II Capital	**58.70**	**70.04**
	Grand Total (Tier I + Tier II)	**418.93**	**508.33**
	a. Adjusted value of funded risk assets i.e. balance sheet items	3307.70	4015.39
	b. Adjusted value of non-funded risk assets i.e. off- balance sheet items	6.10	10.02
	c. Total risk-weighted assets (a+b)	3313.80	4025.41
	d. Percentage of Capital (Tier-I + Tier II) to Risk Weighted Assets	12.64%	12.63%

Deposits

Total deposits as on 31.03.2025 stand at ₹ 8470.49 Crore as against ₹ 7833.62 Crore as on 31.03.2024 with a growth rate of 8.13%.

(₹ in Crore)

Deposit Mix

CASA deposits grew by ₹ 327.34 Crore at 7.17% to reach ₹ 4891.29 Crore as against ₹ 4563.96 Crore as on 31.03.2024. Term Deposits grew by ₹ 309.53 Crore to reach a level of 3579.20 Crore at 9.47% growth as against

₹ 3269.67 Crore as on 31.03.2024. The share of CASA Deposits to total deposits decreased from 58.26% as on 31.03.2024 to 57.75% as on 31.03.2025.

(₹ in Crore)

Deposit mix	2022-23	2023-24	2024-25
Current A/c	**151.71**	**171.02**	**200.84**
Growth	-2.78	19.31	29.82
Growth %age	-1.80%	12.73%	17.44%
Savings Bank A/c	**3988.58**	**4392.93**	**4690.46**
Growth	378.69	404.35	297.53
Growth %age	10.49%	10.14%	6.77%
Total CASA	**4140.29**	**4563.95**	**4891.29**
Growth	375.91	423.66	327.34
Growth %age	9.99%	10.23%	7.17%
Term Deposits	**2977.47**	**3269.67**	**3579.20**
Growth	256.31	292.20	309.53
Growth %age	9.42%	9.81%	9.47%
Total deposits	**7117.76**	**7833.62**	**8470.49**
Growth	632.22	715.86	636.87
Growth %age	9.75%	10.06%	8.13%

DICGC Premium

The Bank is paying a premium to Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation (DICGC) in due time regarding deposit insurance. Bank has paid Rs. 11.41 crores premium to DICGC during FY 2024-25 as compared to Rs. 10.41 crores during FY 2023-24.

Borrowings

The total refinance availed in this financial year is ₹ 251.08 crore and aggregate borrowings of the Bank as on 31st March 2025 stood at ₹ 284.41 crore.

Investments

The total investment portfolio of the Bank has decreased to ₹ 3671.25 Crore as on 31.03.2025 from the previous year's level of ₹ 3722.41 Crore by ₹ 51.16 Crore @ -1.37%. Bank has no MTM Loss on AFS Category of Investment as on 31.03.2025. Modified duration for Govt. Securities including SDL & SSDL is 3.75 years.

(₹ in Crore)

S.No.	Particulars	Amount	% of total investment	% of NDTL
1	SLR	3548.93	96.67%	NA
1.1	AFS	2003.76	54.58%	23.67%
1.2	HTM	1545.17	42.09%	18.25%
2	SSDL	25.21	0.69%	NA
3	Mutual Fund	44.37	1.21%	NA
4	Bonds	52.74	1.44%	NA

CRR and SLR

The Bank has complied with the regulatory requirements for the maintenance of adequate balances towards CRR and SLR. There is a well-laid-down system of assessing the CRR and SLR requirements considering the NDTL. There was no default in the maintenance of adequate balances during the year. The Bank has kept ₹ 339.63 crores in CRR and ₹ 3604.35 crores in SLR as on 31.03.2025.

Bank has ₹ 1545.17 crores of Govt. securities in HTM Category and ₹ 2003.76 crores in AFS category. Bank has earned interest income of ₹ 263.10 crore during FY 2024-25 from SLR investment. Average Yield on SLR Investment is 7.33% for the FY 2024-25. Bank has earned profit of ₹ 1.96 crore from sale of Govt. Securities during FY 2024-25.

Credit Portfolio

The credit portfolio of the Bank rose by 22.16% to ₹ 4577.95 Crore during the financial year ended on 31.03.2025 from the previous year's level of ₹ 3747.64 Crore, thus showing an absolute growth of ₹ 830.31 Crore. Priority sector advances grew at 23.81% in FY 2024-25 to reach ₹ 2641.76 Crore.

BORROWING FROM AGENCIES BY UGB DURING 2023-24 & 2024-25

(₹ in Crore)

S.No.	Particulars	TYPE	2022-23	O/S 31-03-2023	2023-24	O/S 31-03-2024	2024-25	O/S 31-03-2025
1	NABARD	ST-SAO	67.00	67.00	116.00	95.00	107.15	107.15
2	NABARD	LTCRF	14.50	30.47	26.00	43.61	30.00	61.61
3	NABARD	NRLM	-	0.58	-	-	-	-
4	NABARD	ST-Others	-	-	50.00	50.00	112.00	112
5	**NABARD TOTAL**		**81.50**	**98.05**	**-**	**188.61**	**249.15**	**280.77**
6	NSKFDC		-	-	-	-	0.40	0.35
7	NHFDC		0.042	0.083	0.06	0.093	0.12	0.17
8	NSTFDC		0.61	1.64	0.32	0.89	0.51	1.07
9	NBCFDC		0.21	0.46	0.33	0.74	0.35	0.99
10	NSFDC		-	-	0.67	0.65	0.55	1.06
	TOTAL		**82.37**	**100.23**	**193.38**	**190.98**	**251.08**	**284.41**

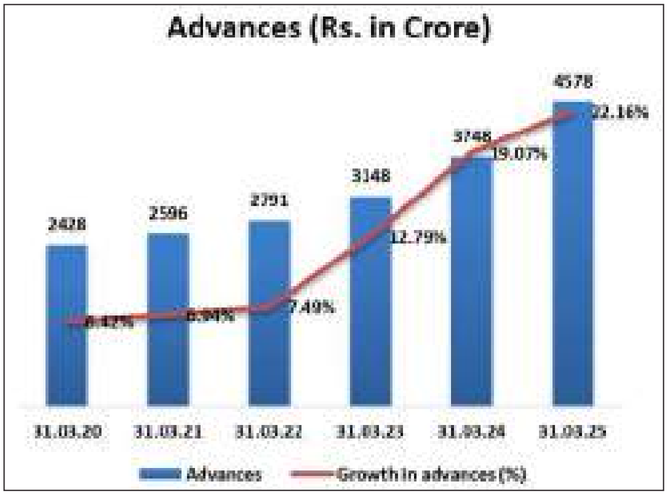

Credit to Agriculture

Total credit to agriculture and allied activities stood at ₹ 695.05 Crore as on 31.03.2025 as against Rs. 557.55 Crore as on 31.03.2024 and recorded a growth of 24.66%. The Bank has disbursed ₹ 535.87 Crore to agriculture sector during CFY as compared to ₹ 419.75 Crore during FY 2023-24.

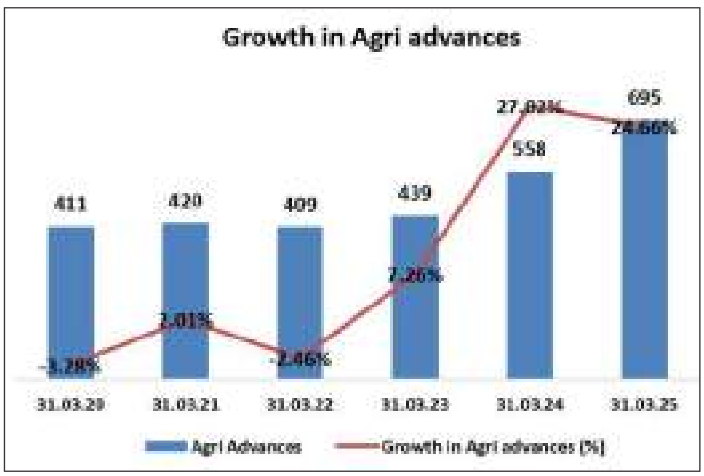

New Agri Product

Bank has also introduced Gud-Khaandsari Smridhi Yojna & E-NWR receipt scheme during FY 2024-25.

Crop loans under the Kisan Credit Card

The Bank has made all efforts to disburse agri-credit through Kisan Credit Cards exploiting the available limited potential to its maximum. We have 42872 KCC accounts as on 31.03.2025 out of which 5003 new KCCs were issued in FY 24-25. During the FY 2024-25, we have disbursed an amount of ₹ 222.43 Crore to KCC cardholders with a total outstanding of ₹ 341.75 Crores.

Interest Subvention

As per Government of India guidelines, Bank is charging 7% interest rate to all crop loan borrowers up to ₹ 3.00 lakhs and accordingly claimed an amount of ₹ 23.96 lakhs towards 1.5% interest subvention (Scheme Year 2022-23) and ₹ 116.40 lakhs towards 1.5% interest subvention (Scheme Year 2023-24) from GOI during the FY 2024-25.

As per the directives of Government of India, we have passed on the benefit relating to PRI (Prompt Repayment Incentive) of 3% to the tune of ₹ 1.46 crore to the KCC holders and claim have been submitted to NABARD accordingly.

Joint Liability Groups (JLGs)

JLG serves as an important tool for augmenting flow of credit to landless farmers cultivating land as tenant farmers and small/marginal farmers and other poor individuals for taking up farm, off-farm and non-farm activities. As on 31.03.2025, the total JLGs accounts financed to 5221 with the outstanding amount of ₹ 23.74 Crores. During the FY 24-25, 686 fresh accounts were financed to the tune of ₹ 4.92 crores.

Self Help Groups

The Bank has given special thrust on formation and credit linkage of Self Help Groups with a view of increasing awareness among the rural masses especially the Women's Self Help Groups regarding fulfillment of their urgent credit needs in a better and a cost effective manner. Our Bank has financed 12636 Self Help Groups with an outstanding portfolio of ₹ 154.36 Crore as on 31.03.2025. During the FY 2024-25 Credit Limits worth ₹ 218.25 Crore have been sanctioned to 5681 groups, out of which 5389 groups were under NRLM and 292 groups other than NRLM have been credit linked with the Bank.

DAY National Rural Livelihood Mission (DAY-NRLM) - Aajeevika – Interest Subvention Scheme

Our Bank has implemented NRLM Scheme as per the guidelines issued by NABARD. The Mission aims at creating an efficient and effective institutional platform of the rural poor enabling them to increase household income through sustainable livelihood enhancement and improved access to financial services.

Under the Scheme, all Women DAY NRLM SHGs promoted by Central Government or State Government Line Departments or NABARD, which are linked with our Bank, are eligible to avail the benefits of the Scheme. As per the Scheme, Interest Subvention Scheme on Credit to Women SHG during the Year 2024-25 is applicable in all districts of the country. All such Women SHGs in all districts have been extended credit at 7% rate of interest upto 3 Lakhs and Government would subvent at uniform rate of 4.50% per Annum Apart from this, for Loan above 3 lakh and up to 5 lakh Government would subvent at uniform rate of 5%.